Hans India, Hyderabad, 21/02/2026
Page No: 7, Size: 40.80cm × 18.12cm

Medical staff told to treat leprosy patients with compassion for curative results

NHRC Leprosy special monitor Pradeepta Kumar Nayak visits RR district

Esa Bin Abdul Rehman
Rangareddy

A two-day visit of the National Human Rights Commission (NHRC) Leprosy Special Monitor Pradeepta Kumar Nayak to oversee the measures by the government to control leprosy and ensure better treatment in Ranga Reddy district concluded on Friday. He reviewed the implementation of leprosy control measures in the district and the measures to protect the rights of the affected people. "Protection rights, dignity and social equality of people affected by leprosy is the primary responsibility of NHRC," he said, addressing officials from the Medical department during a district- level review meeting on his first day of the visit at the collectorate.

While elaborating advanced medication therapy to treat, he said, "Leprosy is an ancient disease and is completely curable if detected timely and improved multi-drug treatment (MDT) is provided. However, if detected late, it can lead to permanent disability."

He suggested that leprosy should not be considered as a mere medical anomaly, but a social problem linked to misconceptions and social discrimination. To counter this, a rights-based approach should be adopted with awareness among people about early detection, easy access to health services, social security schemes and most importantly the coordination between departments. Nayak expressed satisfaction over the facilities being provided to leprosy victims by various departments in the district. Later, the DMHO apprised the LSM with details of leprosy control programme being implemented in the district through a power-point presentation. "A complete eradication of leprosy, also known as Hansen's disease, can be possible if officers of all the departments work in coordination and with a sense of humanity through ensuring that all benefits of government schemes be reached to patients," he maintained.

Joint Director of the Leprosy Programme Dr. John Babu explained the aspects behind spreading leprosy, symptoms, treatment and role everyone can play in controlling the contagion. Additional Collector K. Srinivas, Additional DMHO Dr Papa Rao, DRO Sangeetha, besides officers from different departments, were present. Later Dr. Nayak visited the PHCs at Balapur and Lemur to enquire about the services being provided to patients. He met the staff of the PHCs and ASHA workers and emphasised

the need to treat leprosy patients with love and compassion; steps to be taken to protect their rights. He interacted with the patients; saw records of patients at PHCs and made suggestions to the staff.

Dr. Nayak was accompanied by the State Leprosy Officer Dr. John Babu, DMHO Dr Lalita Devi, Additional DMHO (leprosy) Dr Papa Rao, Kandukur sub-district medical and health officer Dr Geeta, medical officers Doctors Balamani, Swaroopa, district para medical officer Sulochana.

Telegraph, Kolkata, 21/02/2026
Page No: 4, Size: 4.74cm × 12.36cm

NHRC seeks report on Delhi scribe

OUR BUREAU

New Delhi: The National Human Rights Commission has taken suo motu cognisance of a media report that a woman journalist was subjected to physical and sexual assault by a mob while she was on a professional assignment to cover a students' protest against the UGC regulations in the North Campus of Delhi University on February 13.

The commission has issued a notice to the Delhi police commissioner, calling for a detailed report on the matter within two weeks, as it has observed that the contents of the news report, if true, raise a serious issue of violation of the human rights of the victim.

Amar Ujala (My City), Bahraich, 21/02/2026
Page No: 3, Size: 4.79cm × 13.71cm

जल्द ही बाल श्रम मुक्त होगा जिला

बहराइच। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (बाल एवं बंधुआ श्रम) के स्पेशल मॉनिटर धनंजय टिंगल ने शुक्रवार को जिले का दौरा किया। कलेक्ट्रेट सभागार में विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करते हुए उन्होंने निर्देश दिए कि बाल श्रम को जड़ से मिटाने के लिए सभी विभाग जल्द आपसी तालमेल के साथ कड़े कदम उठाएं।

स्पेशल मॉनिटर ने की समीक्षा

उन्होंने कहा कि बाल श्रम और बंधुआ श्रम जैसी कुप्रथाओं को रोकने के लिए केवल प्रशासनिक कार्रवाई काफी नहीं है, बल्कि समाज को जागरूक करना भी अनिवार्य है। उन्होंने स्कूलों, ग्राम पंचायतों और शहरी वार्डों में विशेष अभियान चलाकर लोगों को कानूनी प्रावधानों और बाल श्रम के दुष्परिणामों की जानकारी देने का निर्देश दिया।

अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि मुक्त कराए गए बच्चों की शिक्षा और सरकारी योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करने के लिए निरंतर निगरानी (मॉनिटरिंग) की जाए, ताकि वे दोबारा मजदूरी की ओर न लौटें। बैठक में अक्षय त्रिपाठी, राम नयन सिंह, मुकेश चंद्र, देवेंद्र पाल सिंह व सिद्धार्थ मोदियानी सहित विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे। (संवाद)

Amrit Vichar, Lucknow, 21/02/2026
Page No: 6, Size: 31.30cm × 16.80cm

प्रधान लिपिक निलंबित, प्रबंधक को नोटिस

संवाददाता कुशीनगर

700 छात्रों को बोर्ड परीक्षा से बाहर किए जाने का मामला

अमृत विचार: पडरौना में गोस्वामी तुलसी दास इंटर कॉलेज के 700 पत्राचार परीक्षार्थियों को परीक्षा से वंचित करने के मामले में प्रधान लिपिक पर मुकदमा दर्ज कर निलंबन की कार्रवाई की गई है। वहीं दूसरी ओर मामले में नोडल अधिकारी के खिलाफ अब तक कार्रवाई लंबित हैं। जबकि निदेशालय द्वारा जिला विद्यालय निरीक्षक को दिये आदेश में नोडल अधिकारी व प्रधान लिपिक दोनों के खिलाफ अभियोग पंजीकृत कराने का उल्लेख किया गया है। डीआईओएस के इस कार्रवाई के पीछे खुद को और दोषियों को बचाने की बात कही जा रही है। वजह यह है कि इस पूरे प्रकरण में डीआईओएस दफ्तर की जबाबदेही नोडल अधिकारी व प्रधान लिपिक से अधिक है। यही वजह है कि पूरे घटनाक्रम में सबसे बड़ा सवाल डीआईओएस कार्यालय की भूमिका को लेकर उठ रहा है। पत्राचार शिक्षा संस्थान, प्रयागराज उत्तर प्रदेश के अपर शिक्षा निदेशक सीएल चौरसिया द्वारा जिला विद्यालय निरीक्षक को जारी आदेश पत्र मे गोस्वामी तुलसीदास इंटर कालेज के नोडल अधिकारी विकास मणि त्रिपाठी और प्रधान लिपिक ज्ञान प्रकाश पाठक के विरुद्ध उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अधिनियम-2024 की सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कराए जाने का निर्देश स्पष्ट शब्दों में दिया गया है। इसके बावजूद जिला विद्यालय निरीक्षक श्रवण कुमार गुप्त ने प्रबंधक व प्रधानाचार्य के माध्यम से केवल प्रधान लिपिक ज्ञान प्रकाश पाठक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराकर बिना नोटिस जारी किये निलंबन के कार्रवाई की संस्तुति कर दी जबकि नोडल अधिकारी पर अब तक कार्रवाई नही हुई। विभाग से जुडे जानकारों की माने तो परीक्षा आवेदन पत्र अंतिम रूप से डीआईओएस कार्यालय के माध्यम से ही बोर्ड को भेजे जाते हैं। ऐसे मे 700 परीक्षार्थियों के फॉर्म अपूर्ण व त्रुटिपूर्ण थे, तो इसमें डीआईओएस कार्यालय अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकता।

मानवाधिकार आयोग भी सख्त

इस पूरे मामले पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने भी संज्ञान लिया है। सदस्य प्रियांक कानूनगो की अध्यक्षता वाली पीठ ने उत्तर प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव को नोटिस जारी कर दो सप्ताह में विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। जिसके चलते यह मामला अब सिर्फ विभागीय नहीं रहा।

Aaj, Lucknow, 21/02/2026
Page No: 7, Size: 9.76cm × 14.45cm

मानवाधिकार आयोग के स्पेशल मॉनिटर का आगमन

बहराइच। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (बाल एवं बधुआ श्रम) के स्पेशल मॉनिटर धनन्जय टिंगल ने जनपद भ्रमण के दौरान कलेक्ट्रेट स्थित जिलाधिकारी कक्ष में जिलाधिकारी अक्षय त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक राम नयन सिंह, मुख्य विकास अधिकारी मुकेश चन्द्र, मुख्य राजस्व अधिकारी देवेन्द्र पाल सिंह, सहायक श्रम आयुक्त सिद्धार्थ मोदियानी व अन्य अधिकारियों तथा विभिन्न स्वयं सेवी संस्थाओं के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करते हुए बाल एवं बंधुआ श्रम के विभिन्न प्रावधानों को प्रभावी रूप से लागू करने तथा जनपद को बाल श्रम एवं बंधुआ श्रम की कुप्रथा से मुक्त कराने हेतु विभिन्न विभागों द्वारा की जा रही कार्यवाही की समीक्षा करते हुए निर्देशित किया कि सभी सम्बन्धित विभागों को समन्वय के साथ बाल श्रम उन्मूलन हेतु प्रभावी कार्यवाही की जाय। श्री टिंगल ने सुझाव दिया कि बाल श्रम एवं बंधुआ श्रम जैसी कुप्रथा पर प्रभावी अंकुश के लिए आमजन को जागरूक किया जाय। बैठक से पूर्व स्पेशल मॉनिटर श्री टिंगल द्वारा लोक निर्माण विभाग के निरीक्षण भवन में बाल श्रम से अवमुक्त कराए गए बच्चों एवं उनके अभिभावकों से वार्ता करते हुए कुशल क्षेम जाना तथा उन्हें मिल रहे सरकारी योजनाओं के लाभों के संबंध में भी जानकारी प्राप्त की।

Dainik Bhaskar, Lucknow, 21/02/2026
Page No: 14, Size: 7.04cm × 19.34cm

मानवाधिकार आयोग के स्पेशल मॉनिटर का आगमन

बहराइच ब्यूरो। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (बाल एवं बधुआ श्रम) के स्पेशल मॉनिटर धनन्जय टिंगल ने जनपद भ्रमण के दौरान कलेक्ट्रेट स्थित जिलाधिकारी कक्ष में जिलाधिकारी अक्षय त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक राम नयन सिंह, मुख्य विकास अधिकारी मुकेश चन्द्र, मुख्य राजस्व अधिकारी देवेन्द्र पाल सिंह, सहायक श्रम आयुक्त सिद्धार्थ मोदियानी व अन्य अधिकारियों तथा विभिन्न स्वयं सेवी संस्थाओं के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करते हुए बाल एवं बंधुआ श्रम के विभिन्न प्रावधानों को प्रभावी रूप से लागू करने तथा जनपद को बाल श्रम एवं बंधुआ श्रम की कुप्रथा से मुक्त कराने हेतु विभिन्न विभागों द्वारा की जा रही कार्यवाही की समीक्षा करते हुए निर्देशित किया कि सभी सम्बन्धित विभागों को समन्वय के साथ बाल श्रम उन्मूलन हेतु प्रभावी कार्यवाही की जाय। श्री टिंगल ने सुझाव दिया कि बाल श्रम एवं बंधुआ श्रम जैसी कुप्रथा पर प्रभावी अंकुश के लिए आमजन को जागरूक किया जाय।

Daily News Activist, Lucknow, 21/02/2026
Page No: 10, Size: 26.38cm × 22.01cm

बंधुआ श्रम कुप्रथा रोक कार्रवाई की हुई समीक्षा

बहराइच (डीएनएन)। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (बाल एवं बधुआ श्रम) के स्पेशल मॉनिटर धनन्जय टिंगल ने जनपद भ्रमण के दौरान कलेक्ट्रेट स्थित कक्ष में जिलाधिकारी अक्षय त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक राम नयन सिंह, मुख्य विकास अधिकारी मुकेश चन्द्र, मुख्य राजस्व अधिकारी देवेन्द्र पाल सिंह, सहायक श्रम आयुक्त सिद्धार्थ मोदियानी व अन्य अधिकारियों तथा विभिन्न स्वयं सेवी संस्थाओं के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करते हुए बाल एवं बंधुआ श्रम के विभिन्न प्रावधानों को प्रभावी रूप से लागू करने तथा जनपद को बाल श्रम एवं बंधुआ श्रम की कुप्रथा से मुक्त कराने हेतु विभिन्न

- मानवाधिकार आयोग के स्पेशल मॉनिटर ने की बैठक

विभागों द्वारा की जा रही कार्यवाही की समीक्षा करते हुए निर्देशित किया कि सभी सम्बन्धित विभागों को समन्वय के साथ बाल श्रम उन्मूलन हेतु प्रभावी कार्यवाही की जाय।

श्री टिंगल ने सुझाव दिया कि बाल श्रम एवं बंधुआ श्रम जैसी कुप्रथा पर प्रभावी अंकुश के लिए आमजन को जागरूक किया जाय। बैठक से पूर्व स्पेशल मॉनिटर श्री टिंगल द्वारा लोक निर्माण विभाग के निरीक्षण भवन में बाल श्रम से अवमुक्त कराए गए बच्चों एवं उनके अभिभावकों से वार्ता करते हुए कुशल क्षेम जाना व उन्हें मिल रहे सरकारी योजनाओं के लाभों के संबंध में भी जानकारी प्राप्त की।

घर के अंदर फांसी लगाकर युवक ने की आत्महत्या

रूपईडीहा बहराइच। थाना रूपईडीहा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम चरदा में गुरुवार की रात एक युवक ने घर के अंदर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आवश्यक विधिक कार्रवाई शुरू कर दी। प्राप्त जानकारी के अनुसार अजय चौरसिया (28) पुत्र कमल चौरसिया निवासी ग्राम चरदा, थाना रूपईडीहा, जनपद बहराइच ने 20 फरवरी को रात करीब 1:00 बजे अपने घर के अंदर गमछे के सहारे लटककर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि जिस कमरे में युवक ने यह कदम उठाया, उसका किवाड़ अंदर से बंद था। घटना के समय घर में मृतक की मां, पत्नी और बहन मौजूद थीं। काफी देर तक कमरे का दरवाजा नहीं खुलने पर परिजनों को आशंका हुई। बाद में दरवाजा खुलवाने पर युवक फांसी के फंदे से लटका मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

Prabhat Khabar, Ranchi, 21/02/2026
Page No: 10, Size: 19.90cm × 10.74cm

नवजात को बेचने के मामले में एनएचआरसी सख्त

पलामू डीसी को समन जारी करने का निर्देश

वरीय संवाददाता, रांची

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने पलामू जिला के लेस्लीगंज प्रखंड के लोटवा गांव में नवजात शिशु को 50 हजार रुपये में बेचने के आरोप से जुड़े मामले में कड़ा रुख अपनाया है. आयोग ने पलामू डीसी को सशर्त समन जारी करने का निर्देश दिया है.

मामले में शिकायतकर्ता बाल अधिकार कार्यकर्ता ने आरोप लगाया था कि गंभीर आर्थिक तंगी और इलाज के अभाव में मां पिंकी देवी को अपने नवजात शिशु बेचने के लिए विवश होना पड़ा. परिवार के पास आधार और राशन कार्ड जैसे बुनियादी दस्तावेज नहीं थे. वे मंदिर के शेड में रहने को विवश थे. इसे संविधान के अनुच्छेद 23 के तहत मानवाधिकारों का गंभीर उल्लंघन बताया गया. आयोग की पीठ ने 11 सितंबर-2025 को मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 12 के तहत संज्ञान लेते हुए पलामू के डीसी से दो सप्ताह में एक्शन टेकन रिपोर्ट मांगी थी. नौ दिसंबर 2025 को प्रस्तुत रिपोर्ट में जिला प्रशासन ने बताया कि पिंकी देवी के बच्चों का नामांकन प्राथि और आंगनबाड़ी केंद्र में किया गया है. पोषण आहार और स्वास्थ्य जांच की व्यवस्था की गयी है. मतदाता पहचान पत्र व जन्म प्रमाण पत्र जारी किये गये हैं. इसके अलावा आधार पंजीकरण की प्रक्रिया चल रही है. परिवार भूमिहीन है और आवास योजना का लाभ दिलाने के लिए भूमि आवंटन की प्रक्रिया शुरू की गयी है. मामले में 06 जनवरी-2026 को आयोग ने भूमि आवंटन पर अद्यतन रिपोर्ट चार सप्ताह में देने का निर्देश दिया था, लेकिन रिपोर्ट समय पर प्रस्तुत नहीं की गयी. इसे गंभीरता से लेते हुए आयोग ने मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 13 के तहत डीसी पलामू को 27 मार्च 2026 को सुबह 11.30 बजे नयी दिल्ली स्थित मानवाधिकार भवन में व्यक्तिगत रूप से या अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित होने के लिए सशर्त समन जारी करने का निर्देश दिया.

> आर्थिक तंगी और इलाज के अभाव में मां पिंकी देवी को अपने नवजात शिशु बेचने के लिए विवश होना पड़ा था

Dainik Jagran, Kanpur, 21/02/2026
Page No: 11, Size: 40.69cm × 29.77cm

हिरासत में मौत पर मुआवजा तय करने की नीति बनाए

- पीलीभीत जिला जेल में बंदी की मौत पर परिवार को दस लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश
- हाई कोर्ट की टिप्पणी, हिरासत में यातना मानव गरिमा पर सीधा प्रहार, राज्य की जवाबदेही तय

विधि संवाददाता, जागरण, लखनऊ : इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने हिरासत में मृत्यु (कस्टोडियल डेथ) के मामलों में मृतक के परिवार को मुआवजा देने के लिए राज्य सरकार को स्पष्ट दिशानिर्देश (गाइडलाइंस) तैयार करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही न्यायालय ने पीलीभीत में हुई एक बंदी की मौत के मामले में उसके स्वजन को तीन सप्ताह के भीतर दस लाख रुपये मुआवजा देने का निर्देश भी दिया है।

यह आदेश न्यायमूर्ति शेखर बी. सराफ तथा न्यायमूर्ति मंजीव शुक्ला की खंडपीठ ने पीलीभीत जिला जेल में याची के पुत्र की अप्राकृतिक मृत्यु से संबंधित याचिका पर पारित किया। याचिका के अनुसार, वर्ष 2016 में पूरनपुर थाने की पुलिस ने दुष्कर्म तथा पाक्सो अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया था। याची का पुत्र करीब तीन वर्ष दस माह तक कारावास में रहा। जमानत मिलने के बाद उसे विचारण न्यायालय में उपस्थित होना था, लेकिन अनुपस्थित रहने पर ट्रायल कोर्ट ने वारंट जारी किया और उसे पुनः गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। 20 फरवरी 2024 को उसकी जेल में मृत्यु हो गई। मजिस्ट्रेट जांच में आत्महत्या की बात सामने आई, लेकिन न्यायालय ने कहा कि मृत्यु राज्य प्राधिकारियों की अभिरक्षा और नियंत्रण में हुई। अभिलेखों से स्पष्ट है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्रदत्त मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है। न्यायालय ने टिप्पणी की कि हिरासत में यातना मानव गरिमा का उल्लंघन है, जो व्यक्ति के आत्मसम्मान और अस्तित्व को मूल से नष्ट कर देती है। जब भी मानव गरिमा आहत होती है, सभ्यता एक कदम पीछे चली जाती है। पुलिस हिरासत और जेलों में बढ़ती यातना और मौत की घटनाएं चिंताजनक हैं तथा विधि के शासन की मूल भावना पर प्रहार हैं। राज्य पर यह कठोर दायित्व है कि वह अपनी अभिरक्षा में रखे गए व्यक्तियों के जीवन और स्वतंत्रता की सुरक्षा सुनिश्चित करे।

उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने पहले मृतक के परिवार को तीन लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया था, जिसका पालन न होने पर याची ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। अब न्यायालय ने दस लाख रुपये मुआवजा देने का स्पष्ट निर्देश दिया है।

प्रदेश के भीतर गाय का परिवहन अपराध नहीं : हाई कोर्ट

विधि संवाददाता, जागरण प्रयागराज : इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि गोवध निरोधक कानून के तहत गाय अथवा गोमांस प्रदेश के बाहर ले जाना अपराध है। प्रदेश के भीतर परिवहन करना अपराध नहीं है। कोर्ट ने दुधारू गाय खरीदकर मऊ जिले में ले जाने वाले वाहन को जब्त करने के जिलाधिकारी बलिया के आदेश को अवैध करार देते हुए रद कर दिया। यह आदेश न्यायमूर्ति एससी शर्मा की एकलपीठ ने मंजीत कुमार मौर्य की पुनरीक्षण याचिका को स्वीकार करते हुए दिया है। याची अधिवक्ता का कहना था कि बोलोरो पिकअप वाहन से एक गाय, चितबड़ा गांव बलिया से मऊ ले जाई जा रही थी। उसे थाना फेफना में पुलिस ने जब्त कर लिया। बलिया पुलिस की इस कार्यवाही के विरुद्ध जिलाधिकारी बलिया के पास आवेदन पत्र दिया गया। जिलाधिकारी बलिया ने अपने आदेश 21 जुलाई 2025 द्वारा वाहन को रिलीज करने से इन्कार कर दिया। जिलाधिकारी बलिया के इस आदेश के विरुद्ध हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी।

Source: https://www.thehindu.com/news/cities/Delhi/nhrc-notice-to-delhi-police-over-assault-on-journalist-on-dus-north-campus/article70656149.ece

NHRC notice to Delhi police over assault on journalist on DU's North Campus

Published - February 21, 2026 01:05 am IST - New Delhi
New Delhi

The National Human Rights Commission (NHRC) on Friday issued notice to Delhi police in a case of alleged physical and sexual assault on a woman journalist by a mob while she was on an assignment to cover a students' protest against the UGC regulations on the North Campus of Delhi University.

According to reports, the incident took place on February 13 when the protesters, after identifying the journalist's caste, began assaulting her. The victim also alleged that some people threatened to parade her naked before she lost consciousness, the NHRC communique said.

It further cited media reports that stated that the victim has alleged that she was specifically targeted because of her caste. She escaped her ordeal with the help of some faculty and women police personnel.

Observing that the case raises serious issue of violation of human rights of the victim, the commission, in a notice to Delhi Police Commissioner, called for a detailed report on the matter within two weeks.

Hans India, Online News, 21/02/2026

Source: https://www.thehansindia.com/telangana/medical-staff-told-to-treat-leprosy-patients-with-compassion-for-curative-results-1050464

Medical staff told to treat leprosy patients with compassion for curative results

Created On: 21 Feb 2026 7:23 AM IST
By Esa Bin Abdul Rehman

Rangareddy: A two-day visit of the National Human Rights Commission (NHRC) Leprosy Special Monitor Pradeepta Kumar Nayak to oversee the measures by the government to control leprosy and ensure better treatment in Ranga Reddy district concluded on Friday. He reviewed the implementation of leprosy control measures in the district and the measures to protect the rights of the affected people. “Protection rights, dignity and social equality of people affected by leprosy is the primary responsibility of NHRC,” he said, addressing officials from the Medical department during a district- level review meeting on his first day of the visit at the collectorate.

While elaborating advanced medication therapy to treat, he said, “Leprosy is an ancient disease and is completely curable if detected timely and improved multi-drug treatment (MDT) is provided. However, if detected late, it can lead to permanent disability.”

He suggested that leprosy should not be considered as a mere medical anomaly, but a social problem linked to misconceptions and social discrimination. To counter this, a rights-based approach should be adopted with awareness among people about early detection, easy access to health services, social security schemes and most importantly the coordination between departments. Nayak expressed satisfaction over the facilities being provided to leprosy victims by various departments in the district. Later, the DMHO apprised the LSM with details of leprosy control programme being implemented in the district through a power-point presentation. “A complete eradication of leprosy, also known as Hansen’s disease, can be possible if officers of all the departments work in coordination and with a sense of humanity through ensuring that all benefits of government schemes be reached to patients,” he maintained.

Joint Director of the Leprosy Programme Dr. John Babu explained the aspects behind spreading leprosy, symptoms, treatment and role everyone can play in controlling the contagion. Additional Collector K. Srinivas, Additional DMHO Dr Papa Rao, DRO Sangeetha, besides officers from different departments, were present. Later Dr. Nayak visited the PHCs at Balapur and Lemur to enquire about the services being provided to patients. He met the staff of the PHCs and ASHA workers and emphasised the need to treat leprosy patients with love and compassion; steps to be taken to protect their rights. He interacted with the patients; saw records of patients at PHCs and made suggestions to the staff.

Dr. Nayak was accompanied by the State Leprosy Officer Dr. John Babu, DMHO Dr Lalita Devi, Additional DMHO (leprosy) Dr Papa Rao, Kandukur sub-district medical and health officer Dr Geeta, medical officers Doctors Balamani, Swaroopa, district para medical officer Sulochana.

Source: https://thelegalaffair.com/news/437-custodial-deaths-under-scrutiny-jharkhand-high-court-seeks-accountability-on-mandatory-judicial-inquiries/

437 Custodial Deaths Under Scrutiny: Jharkhand High Court Seeks Accountability on Mandatory Judicial Inquiries

20/02/2026, 8 minutes ago

437 Custodial Deaths Under Scrutiny: Jharkhand High Court Seeks Accountability on Mandatory Judicial Inquiries

Introduction:

In Md. Mumtaz Ansari v. State of Jharkhand through Chief Secretary, Ranchi & Others, W.P. (PIL) No. 1218 of 2022, the Jharkhand High Court took serious note of the State's disclosure that 437 custodial deaths occurred between 2018 and 2025, while there was no clarity in most instances as to whether the mandatory judicial inquiry under Section 176(1-A) of the Code of Criminal Procedure, 1973—now Section 196 of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita (BNSS)—had been conducted. The Division Bench comprising Chief Justice M.S. Sonak and Justice Rajesh Shankar was hearing a public interest litigation filed to ensure strict compliance with the statutory mandate that requires a judicial inquiry by a Judicial Magistrate in every case of death, disappearance, or rape occurring in police or judicial custody. The matter, pending for some time, acquired renewed urgency after an affidavit filed by Mrs. Vandana Dadel, Principal Secretary, Department of Home, Prison and Disaster Management, Government of Jharkhand, enclosed a chart revealing the alarming number of custodial deaths. Although the chart indicated whether the deaths were reported to a Magistrate, it did not clarify whether the legally mandated independent judicial inquiries had actually been conducted. Viewing this omission as significant, the Court directed the Home Secretary to file a comprehensive affidavit detailing compliance not only under the CrPC but also under the corresponding provisions of the BNSS, particularly since the data extended up to 2025. The Court also required disclosure regarding adherence to the National Human Rights Commission (NHRC) guidelines in such cases. The proceedings thus underscore a crucial constitutional concern: whether statutory safeguards intended to ensure transparency and accountability in custodial settings are being meaningfully implemented.

Arguments and Submissions on Behalf of the Petitioner:

The petitioner, represented by Md. Shadab Ansari, approached the High Court through a public interest litigation, contending that the State machinery was not fully complying with the mandatory provisions of Section 176(1-A) CrPC. It was argued that custodial deaths strike at the very heart of constitutional governance, implicating Articles 21 and 14 of the Constitution of India, which guarantee the right to life and equality before the law. The petitioner emphasized that Section 176(1-A), introduced as a safeguard against abuse of power, mandates that in every case of death, disappearance, or rape in custody, an inquiry must be conducted by the jurisdictional Judicial Magistrate in addition to the police investigation. This provision, it was argued, is not directory but mandatory, and its object is to ensure independent scrutiny of custodial incidents, thereby preventing concealment of foul play and reinforcing public confidence in the justice system. The petitioner expressed grave concern over the State's affidavit, which, while acknowledging 437 custodial deaths over a span of seven years, failed to categorically state whether judicial inquiries were conducted in each case. The absence of clear data, according to the petitioner, pointed towards either non-compliance or administrative opacity, both of which undermine the rule of law. The petitioner further argued that mere reporting of deaths to a Magistrate does not satisfy the statutory requirement; what the law mandates is an independent judicial inquiry. Additionally, the petitioner urged the Court to examine whether the State had complied with the guidelines issued by the National Human Rights Commission (NHRC), which lay down procedural safeguards, including immediate reporting, post-mortem examination by qualified doctors, videography of autopsy, and prompt communication to the Commission. The

petitioner contended that failure to conduct judicial inquiries or adhere to NHRC guidelines would amount to systemic violation of constitutional rights and sought directions for strict compliance, transparency, and accountability.

Submissions on Behalf of the State of Jharkhand:

Appearing for the State, Mr. Gaurav Raj placed reliance on the affidavit filed by Mrs. Vandana Dadel, Principal Secretary, Department of Home, Prison and Disaster Management. The affidavit included a chart detailing 437 custodial deaths between 2018 and 2025. The State submitted that the deaths had been reported to the Magistrate, and investigations were carried out in accordance with prevailing procedures. However, the chart did not comprehensively specify in each case whether a separate judicial inquiry under Section 176(1-A) CrPC had been conducted. The State sought time to file a more detailed affidavit clarifying compliance with the statutory mandate. It was indicated that some deaths were due to natural causes, illness, or suicide, and that police investigations had been undertaken. The State did not dispute the binding nature of Section 176(1-A) CrPC but suggested that compliance may vary depending on the circumstances of each case. Regarding the transition from CrPC to BNSS, the State acknowledged that Section 196 of the BNSS now corresponds to Section 176(1-A) and assured the Court that future compliance would be ensured under the new statutory regime. However, the State did not furnish conclusive data demonstrating that independent judicial inquiries were conducted in all 437 cases. The absence of such clarity prompted the Bench to express concern.

Court’s Analysis and Observations:

The Division Bench carefully examined the statutory framework and reiterated the mandatory character of Section 176(1-A) CrPC. The Court observed that the provision was enacted to strengthen accountability in custodial settings, recognizing that incidents occurring within the confines of police stations or prisons require independent scrutiny. The Court emphasized that the statutory language clearly mandates that, in addition to the police investigation, a judicial inquiry by the jurisdictional Judicial Magistrate must be conducted in cases of custodial death, disappearance, or rape. This dual mechanism is designed to ensure transparency, impartiality, and credibility. The Bench noted that the affidavit filed by the State, while disclosing the number of custodial deaths, did not answer the critical question: whether independent judicial inquiries were held in each case. The Court remarked that information regarding such inquiries is crucial, particularly when the number of custodial deaths is as high as 437. It underscored that mere reporting of a death to a Magistrate does not satisfy the statutory requirement; what is required is an inquiry conducted by the Magistrate. The Court further directed that the affidavit to be filed by the Home Secretary must also clarify compliance with Section 196 of the BNSS, given that the data extended from 2023 to 2025. Additionally, the Court mandated disclosure regarding adherence to NHRC guidelines in custodial death cases. The Bench expressed concern that the current affidavit and chart were unclear as to whether the cause of death had been determined solely by police authorities or whether an independent judicial inquiry had been undertaken. The Court highlighted that statutory safeguards are not mere formalities but essential protections to rule out foul play and uphold constitutional values. It granted the State a final opportunity to file a comprehensive affidavit by March 13, 2026, and listed the matter for further consideration on March 19, 2026.

Judicial Directions and Continuing Oversight:

Rather than disposing of the PIL, the High Court adopted a supervisory approach, reflecting the seriousness of the issue. The Court’s directions were precise: the Home Secretary must file a comprehensive affidavit detailing, for each of the 437 custodial deaths, whether a judicial inquiry under Section 176(1-A) CrPC or Section 196 BNSS was conducted; if not, the reasons must be disclosed. The affidavit must also indicate whether NHRC guidelines were followed. By doing so, the Court signaled that compliance with statutory mandates in custodial matters is non-negotiable. The matter remains pending, underscoring the judiciary’s role as guardian of constitutional rights and overseer of executive accountability in matters involving deprivation of liberty.

Hindustan Times, Online News, 21/02/2026

Source: https://www.hindustantimes.com/cities/lucknow-news/state-absolutely-liable-for-unnatural-custodial-death-alld-hc-orders-10-lakh-relief-101771614576690.html

Allahabad HC orders state govt ₹10-lakh relief over custodial death

A division bench of justice Shekhar B Saraf and justice Manjive Shukla passed the judgement on February 20

Published on: Feb 21, 2026 6:08 AM IST

By HT Correspondent, LUCKNOW

The Lucknow bench of the Allahabad high court on Friday held that the state is “absolutely liable” for the unnatural death of a prisoner in its custody, even if the death is a suicide.

The court said the right to life and human dignity guaranteed under Article 21 of the Constitution is an “intrinsic, inviolable and omnipresent right”, extending even to a person illegally arrested or detained by the state.

A division bench of justice Shekhar B Saraf and justice Manjive Shukla passed the judgement on February 20 while allowing a petition filed by Prema Devi, who sought compensation for the death of her minor son in Pilibhit district jail.

Directing the respondents — the state government and other authorities — to pay compensation of ₹10 lakh to the legal heirs within three weeks, the court also asked the Uttar Pradesh government to frame guidelines for determining compensation.

HT graphic

It said the government must adopt relevant and cogent parameters for awarding compensation in custodial death cases, akin to the multiplier method based on age, income and dependents as provided under the Motor Vehicles Act, 1988.

According to the judgment, the petitioner’s son, an undertrial in a Pocso case, died by suicide on February 20, 2024. His body was found hanging from the ventilator of a prison toilet.

The National Human Rights Commission (NHRC) had earlier recommended compensation of ₹3 lakh. As it was not paid, the petitioner approached the high court.

The petitioner alleged the deceased was subjected to torture by police personnel over illegal monetary demands, which ultimately led to his death. The state counsel, however, contended it was a case of suicide and there was no material on record to indicate negligence, misconduct or involvement of the authorities.

The state further submitted that the approved compensation would be released after completion of formalities and receipt of the required budgetary allocation.

The court observed that custodial deaths represent one of the most serious challenges to the protection of fundamental rights within the justice system. It also termed it “flabbergasting” that there is no express constitutional mandate for grant of compensation in cases of unlawful detention or custodial death.

Preliminary steps mandated

The court mandated four preliminary steps to be strictly followed in all future cases of custodial death.

- The jail authorities must immediately inform the deceased’s family members. A panchnama with independent witnesses (panchas) must be prepared on the spot in accordance with Section 174 of the CrPC (corresponding Section 194 of the BNSS) without delay.

- A post-mortem examination must be conducted promptly and the cause of death clearly recorded. Video recording of the post-mortem examination in custodial death cases shall be mandatory.

- An inquest report by the jurisdictional judicial magistrate must be submitted under Section 176 of the CrPC (corresponding Section 196 of the BNSS) after considering witness statements, the post-mortem report and the

panchnama.
- Monetary compensation to the next of kin must be paid in accordance with norms fixed by the National Human Rights Commission (NHRC), taking into account the facts and circumstances of each custodial death case.

Source: https://thenewsmill.com/2026/02/nhrc-takes-suo-motu-cognisance-of-journalist-assault-during-du-protest/

NHRC takes suo motu cognisance of journalist assault during DU protest

Written By: TNM (With ANI Inputs) | Published on: Feb 20, 2026

The National Human Rights Commission (NHRC) has taken suo motu cognisance of a media report alleging that a woman journalist was physically and sexually assaulted by a mob while covering a students' protest against University Grants Commission regulations at the North Campus of Delhi University on February 13.

According to reports, the protesters identified the journalist's caste and began assaulting her. Some individuals allegedly threatened to parade her naked before she lost consciousness.

The NHRC noted that if the contents of the news report are true, they raise a serious issue regarding the violation of the victim's human rights. Consequently, the Commission has issued a notice to the Delhi Police Commissioner, requesting a detailed report within two weeks.

The media report published on February 14 states that the victim journalist alleged she was specifically targeted due to her caste. She reportedly escaped the ordeal with assistance from faculty members and women police personnel.

On February 16, the NHRC also issued notices to the Deputy Commissioner of Police (DCP) for North Delhi and the Vice Chancellor of Delhi University concerning the incident. The Commission directed them to conduct an inquiry and submit an Action Taken Report within two weeks.

The notice outlined the allegations brought forward by the complainant: "The complainant alleged that a woman journalist and content creator was violently assaulted by a mob while she was covering a protest in support of UGC at a Delhi University's North Campus on 13.02.2026. The complainant further alleged that the attackers targeted her on the basis of her caste identity, verbally abused her, and physically assaulted/attacked her, threatened her with violence, and attempted to outrage her."

"The complainant also alleged that the incident amounts to caste-based violence, an attack on the freedom of the press, and a serious violation of her fundamental rights to life, dignity, and personal security. The complainant sought the intervention of the Commission in the matter and requested an impartial investigation, action against the culprits/accused, security/safety, legal aid and compensation to the victim," the letter states.

The Commission added that prima facie these allegations appear to be violations of the victim's human rights.

The NHRC Bench, presided over by Member Priyank Kanoong, took cognisance of the matter under section 12 of the Protection of Human Rights Act, 1993. "The Registry is directed to issue a notice to the DCP, North Delhi and the Vice Chancellor, Delhi University, with directions to get the allegations made in the complaint inquired into and to submit an Action Taken Report within two weeks for perusal of the Commission," the NHRC stated in its notice.

Source: https://timesofindia.indiatimes.com/legal/news/nhrc-seeks-report-from-odisha-human-rights-commission-on-bridge-demand-in-rayagada/articleshow/128592140.cms

NHRC seeks report from Odisha Human Rights Commission on bridge demand in Rayagada

TNN | Feb 20, 2026, 10.30 AM IST

CUTTACK: The National Human Rights Commission (NHRC) has sought from the Odisha Human Rights Commission (OHRC) a report on the lack of a permanent bridge over the Nagabali River, leaving nine tribal villages of Rayagada district.cut off and deprived of basic amenities.

The NHRC also directed the Rayagada district administration to submit a complete and updated report on the long-pending demand for a permanent bridge over the Nagabali River in Kayalansighpur block.

The order was passed while considering on Thursday a complaint by Jeypore based human rights defender Anup Kumar Patro, who cited media reports alleging administrative indifference towards the demands of residents of nine villages in the block.

The villagers have been seeking construction of a permanent bridge to improve connectivity and ensure access to drinking water, education, healthcare and transportation facilities.

The commission had earlier taken cognisance of the matter on October 1, 2025, and sought a detailed report from the district magistrate, Rayagada. In response, the collector and district magistrate, through a communication dated January 8, 2026, forwarded reports from the Zilla Parishad; district manager OSRTC; and regional transport officer, Rayagada. The reports outlined the status of road connectivity, transport services and availability of education, drinking water and health facilities in the affected villages.

However, after perusal of the reports on Thursday, the NHRC asked for “additional and complete report, as earlier directed, by March 29, 2026, for further consideration.” In February 19 order the NHRC further said: “Report be also requisitioned from the Odisha Human Rights Commission as to whether it has taken cognizance of the matter and, if so, the date thereof. “The matter will be listed again after four weeks.

Authorities have been instructed to upload their responses through the HRCNet portal using official login credentials. The commission clarified that reports sent via email will not be entertained, while audio or video material may be sent through Speed Post or by hand.

According to the complaint the villages under three panchayats — Sikaripai (Tolosaja, Uppersaja), Palam (Argonda, Mandipar, Kusabati), and Majhiguda (Minajhola, Kuradi, Katapadu, Raghunathpur) in Kalyansinghpur block — have remained disconnected from the mainland due to the absence of a permanent bridge since Independence. Villagers of these areas are struggling to get access to healthcare, education, drinking water and other essential services. Absence of a bridge continues to isolate them even after 76 years of Independence, the complainant alleged.

Source: https://www.devdiscourse.com/article/headlines/3812096-nhrc-probes-alleged-assault-on-woman-journalist-during-university-protest

NHRC Probes Alleged Assault on Woman Journalist During University Protest

The NHRC has initiated an investigation into allegations of a woman journalist being assaulted by a mob during a protest at Delhi University, reportedly due to her caste. The Commission has demanded a detailed report from Delhi police and university authorities within two weeks.

Devdiscourse News Desk | Updated: 20-02-2026 19:44 IST | Created: 20-02-2026 19:44 IST

The National Human Rights Commission (NHRC) has taken up an urgent inquiry following reports of a woman journalist being physically and sexually assaulted by a mob while covering a student protest against UGC regulations at Delhi University's North Campus. This incident allegedly occurred on February 13.

The reports suggest that the attack was motivated by the journalist's caste, with assailants reportedly threatening extreme humiliation before she eventually fainted. Due to the severe nature of the allegations, the NHRC has officially requested a comprehensive report from the Delhi Police Commissioner within two weeks to assess the situation thoroughly.

A notice has also been addressed to the Deputy Commissioner of Police (DCP) of North Delhi and the Vice Chancellor of Delhi University to conduct an inquiry and submit an Action Taken Report. The Commission emphasized the incident as an infringement on press freedom and a notable violation of the journalist's fundamental human rights, urging swift action for justice.

(With inputs from agencies.)

Orissa Diary, Online News, 21/02/2026

Source: https://orissadiary.com/nhrc-india-takes-suo-motu-cognizance-of-the-reported-physical-and-sexual-assault-on-a-journalist-covering-students-protest-in-the-north-campus-of-delhi-university/

NHRC, India takes suo motu cognizance of the reported physical and sexual assault on a journalist covering students' protest in the North Campus of Delhi University

By: Odisha Diary Bureau
Date: February 20, 2026

The National Human Rights Commission (NHRC), India has taken suo motu cognizance of a media report that a woman journalist was subjected to physical and sexual assault by a mob while she was on a professional assignment to cover a students' protest against the UGC regulations in the North Campus of Delhi University on 13th February 2026. Reportedly, the protesters, after identifying the journalist's caste, began assaulting her and some also threatened to parade her naked before she lost consciousness.

The CommissIon has observed that the contents of the news report, if true, raise a serious issue of violation of the human rights of the victim. Therefore, it has issued a notice to the Delhi Police Commissioner, calling for a detailed report on the matter within two Weeks.

According to the media report, carried on 14th February 2026, the victim journalist has alleged that she was specifically targeted because of her caste. She escaped her ordeal with the help of some faculty and women police personnel.

Source: https://odishatv.in/national/misuse-of-nhrc-name-commission-issues-pan-india-notices-to-states-uts-11135456

Misuse of NHRC name: Commission issues pan-India notices to States, UTs

NHRC, India, has taken suo motu cognizance of the alleged misuse of its name and logo by several NGOs registered under deceptively similar titles, raising concerns over public trust, financial propriety and institutional credibility.

Vikash Sharma

20 Feb 2026 09:23 IST

The National Human Rights Commission (NHRC), India, has taken suo motu cognizance of the alleged misuse of its name and logo by several Non-Governmental Organisations (NGOs) registered under deceptively similar titles, raising concerns over public trust, financial propriety and institutional credibility.

The apex statutory human rights body said it has been receiving complaints from individuals and organisations across the country regarding human rights violations. During scrutiny of these complaints, the Commission observed that certain NGOs have registered themselves under names closely resembling “National Human Rights Commission,” potentially misleading the public into believing they are officially linked to or authorised by the Commission.

NGO Using Similar Name Under Scanner

The issue came into sharper focus after the Commission identified an NGO registered as “National Human Rights Council (NHRC),” reportedly registered with the Government of the National Capital Territory (NCT) of Delhi in 2022.

According to the Commission, publicity materials circulated by the organisation claim registrations with various government entities, including NITI Aayog, the Ministry of Corporate Affairs, and the Ministry of Social Justice and Empowerment. The material also mentions an association with the “Andhra Pradesh Human Rights Council Association.”

A visiting card linked to the organisation reportedly carries the designation “Venkatesh, State Chairman, Karnataka,” further adding to concerns about the use of titles that may imply official authority.

‘Deceptive Nomenclature’ Raises Red Flags

Taking serious note of the matter, the NHRC observed that the use of similar names and designations such as “Chairman” is misleading and capable of creating confusion among citizens and authorities alike.

The Commission emphasised that such deceptive nomenclature may falsely convey the impression that these entities are part of the statutory NHRC or have been formally recognised or authorised by it to handle human rights matters.

It warned that the continued use of such “illusory names” could erode public trust, lead to misuse of mandate, possible misappropriation of funds, and complicate the task of public authorities in distinguishing between a constitutional/statutory body like the NHRC and privately registered NGOs.

Earlier Warnings, Continued Violations

The Commission noted that it had previously raised concerns on various platforms regarding the misuse of its name and logo and had informed relevant authorities to take strict action against such organisations. However, despite these warnings, instances of misuse have continued to surface.

Notices Issued to All States and UTs

In response, the NHRC has issued notices to the Chief Secretaries and Directors General of Police (DGPs) of all States and Union Territories, directing them to:

Identify NGOs and individuals misusing the name “National Human Rights Commission” or operating under deceptively similar names.
Initiate immediate legal action, including cancellation of registrations obtained in violation of norms.
Complete the necessary action within two weeks.
Sensitise registering authorities to remain vigilant and prevent similar cases in the future.
Separate Reports Sought from Karnataka and Delhi
In connection with the specific case of the “National Human Rights Council (NHRC),” the Commission has sought detailed action-taken reports within two weeks from:
The Chief Secretary and Director General of Police, Karnataka; and
The Chief Secretary and Commissioner of Police, Delhi.
The NGO in question is reported to have its office in Karnataka while being registered in Delhi.
Protecting Institutional Integrity
The NHRC’s move underscores its intent to safeguard its statutory mandate and institutional identity from misuse. By taking suo motu cognizance and issuing nationwide directions, the Commission has signalled a stricter approach toward organisations that may attempt to exploit its name or create public confusion under the guise of human rights advocacy.
Further action will depend on reports submitted by state authorities within the stipulated timeframe.

Source: https://newsable.asianetnews.com/india/nhrc-issues-notice-to-delhi-police-over-assault-on-woman-journalist-articleshow-p5xnv4o

NHRC issues notice to Delhi Police over assault on woman journalist

3 Min read
Author : Asianet News Central| ANI
Published : Feb 20 2026, 08:00 PM IST

The NHRC has taken suo motu cognizance of a report about a woman journalist being physically and sexually assaulted by a mob during a student protest at Delhi University. The attack was allegedly caste-based. A notice has been issued to the Delhi Police.

The National Human Rights Commission (NHRC) on Friday took suo motu cognizance of a media report alleging that a woman journalist was subjected to physical and sexual assault by a mob while she was on a professional assignment to cover a students' protest against the UGC regulations in the North Campus of Delhi University on February 13. According to reports, the protesters, after identifying the journalist's caste, allegedly began assaulting her, and some reportedly threatened to parade her naked before she lost consciousness.

The Commission has observed that the contents of the news report, if true, raise a serious issue of violation of the human rights of the victim. Therefore, it has issued a notice to the Delhi Police Commissioner, calling for a detailed report on the matter within two Weeks. According to the media report, carried on February 14, the victim journalist has alleged that she was specifically targeted because of her caste. She escaped her ordeal with the help of some faculty and women police personnel.

NHRC Issues Further Notice to DCP, DU Vice Chancellor

Further, on February 16, the NHRC issued a notice to Deputy Commissioner of Police (DCP) of North Delhi and the Vice Chancellor of Delhi University regarding the recent incident where a female journalist and content creator was allegedly assaulted by a mob at Delhi University during a UGC protest, directing them to make an inquiry into the case and submit an Action Taken Report within two weeks.

Details of the Complaint

The notice detailed the allegations made by the complainant, stating, "The complainant alleged that a woman journalist and content creator was violently assaulted by a mob while she was covering a protest in support of UGC at a Delhi University's North Campus on 13.02.2026. The complainant further alleged that the attackers targeted her on the basis of her caste identity, verbally abused her, and physically assaulted/ attacked her, threatened her with violence, and attempted to outrage her."

"The complainant also alleged that the incident amounts to caste-based violence, an attack on the freedom of the press, and a serious violation of her fundamental rights to life, dignity, and personal security. The complainant sought theintervention of the Commission in the matter and requested an impartial investigation, action against the culprits/accused, security/safety, legal aid and compensation to the victim," the letter reads.

Commission's Directive

It added that Prima Facie the allegations seem to be violations of the human rights of the victim. As per the letter, the Bench of the National Human Rights Commission, which is presided over by Priyank Kanoong, Member, took cognizance u/s 12 of the Protection of Human Rights Act, 1993, in the matter. "The Registry is directed to issue a notice to the DCP, North Delhi and the Vice Chancellor, Delhi University, with directions to get the allegations made in the complaint inquired into and to submit an Action Taken Report within two weeks for perusal of the Commission," the NHRC stated in the notice. (ANI)

(Except for the headline, this story has not been edited by Asianet Newsable English staff and is published from a syndicated feed.)

Source: https://jharkhandstatenews.com/article/top-stories/10961/nhrc-takes-suo-motu-cognizance-of-misuse-of-its-name-and-logo-by-ngos-issued-notices-to-css-of-all-states-uts

NHRC takes suo motu cognizance of misuse of its name and logo by NGOs, issued notices to CSs of all states, UTs

Administrator| 20 February 2026

The National Human Rights Commission (NHRC), India has been receiving complaints from individual complainants as well as Non-Governmental Organisations (NGOs) across the country alleging violation of human rights.

While examining these complaints, the Commission has observed that several NGOs have got themselves registered under names deceptively similar to that of the National Human Rights Commission (NHRC).

Recently, the Commission came across an NGO registered as “National Human Rights Council (NHRC)”, reportedly registered with the Government of NCT of Delhi in 2022.

Its publicity material claims, “Registered by Govt. of NITI Aayog”, “Registered by Ministry of Corporate Affairs, India”, “Registered under Ministry of Social Justice and Empowerment, Government of India” and association with “Andhra Pradesh Human Rights Council Association”. A visiting card apparently related to the said organisation also bears the inscription “Venkatesh, State Chairman, Karnataka”.

Considering the gravity of the matter, it has taken suo motu cognizance of the matter. It has observed that the name adopted and the designation “Chairman” is misleading and creates confusion.

Deceptive nomenclature misleads the public into believing that these organisations are either part of the National Human Rights Commission or recognised/ authorised by it to deal with human rights issues.

The Commission is of the view that continuation of such illusory names may erode public trust, lead to misuse of mandate, possible misappropriation of funds and create confusion for public authorities in distinguishing between a statutory body like NHRC and NGOs.

The Commission had earlier expressed concern through various platforms regarding the misuse of its name and logo and informed the authorities concerned to take action against the people behind such dubious organisations. However, violations continue to come to its notice.

Therefore, the Commission has issued notices to the Chief Secretaries and Director Generals of Police of all the States/ UTs to identify such NGOs/ individuals misusing the name of the National Human Rights Commission or using names deceptively similar to it and take immediate legal action within two weeks, including cancellation of registrations obtained in violation of norms. They have also been asked to sensitise registering authorities to remain vigilant and take necessary action against defaulters.

Additionally, in the instant matter of National Human Rights Council (NHRC), the Chief Secretary and the Director General of Police, Karnataka and the Chief Secretary and the Commissioner of Police, Delhi have been further directed to submit reports within two weeks regarding the action taken against the NGO, having its office in Karnataka and registered in Delhi.

Source: https://timesofindia.indiatimes.com/city/bhubaneswar/nhrc-asks-ohrc-for-report-on-lack-of-permanent-bridge-over-nagabali-river/amp_articleshow/128609291.cms

NHRC asks OHRC for report on lack of permanent bridge over Nagabali river

Lalmohan Patnaik | TNN | Feb 20, 2026, 18:24 IST

Cuttack: The National Human Rights Commission (NHRC) has sought from the Odisha Human Rights Commission (OHRC) a report on the lack of a permanent bridge over the Nagabali river leaving nine tribal villages of Rayagada district cut off and depriving them of basic amenities.

The NHRC also directed the Rayagada administration to submit a complete and updated report on the long-pending demand for a permanent bridge over the Nagabali river in Kalyanasingpur block.

The order was passed on Thursday while considering a complaint by Jeypore-based human rights defender Anup Kumar Patro, who cited media reports alleging administrative indifference towards the demands of residents of the nine villages. The villagers have been seeking construction of a permanent bridge to improve connectivity and ensure access to drinking water, education, healthcare and transportation facilities.

The commission had earlier taken cognisance of the matter on Oct 1, 2025, and sought a detailed report from the district magistrate, Rayagada. In response, the collector and district magistrate, through a communication dated Jan 8, 2026, forwarded reports from the zilla parishad, district manager, OSRTC and regional transport officer, Rayagada. The reports outlined the status of road connectivity, transport services and availability of education, drinking water and health facilities in the affected villages.

However, after perusal of the reports on Thursday, the NHRC asked for “additional and complete report, as earlier directed, by March 29, 2026, for further consideration.” In the Feb 19 order, the NHRC further said: “Report be also requisitioned from the Odisha Human Rights Commission as to whether it has taken cognizance of the matter and, if so, the date thereof.” The matter will be listed again after four weeks.

Authorities have been instructed to upload their responses through the HRCNet portal using official login credentials. The commission clarified that reports sent via email will not be entertained, while audio or video material may be sent through speed post or by hand.

According to the complaint the villages under three panchayats — Sikaripai (Tolosaja, Uppersaja), Palam (Argonda, Mandipar, Kusabati), and Majhiguda (Minajhola, Kuradi, Katapadu, Raghunathpur) in Kalyansinghpur block — have remained disconnected from the mainland due to the absence of a permanent bridge since Independence.

Villagers of these areas are struggling to get access to healthcare, education, drinking water and other essential services. Absence of a bridge continues to isolate them even after 76 years of Independence, the complainant alleged.

Source: https://www.devdiscourse.com/article/entertainment/3812004-human-rights-commission-demands-report-on-journalists-assault-at-du-protest

Human Rights Commission Demands Report on Journalist's Assault at DU Protest

The National Human Rights Commission (NHRC) has issued a notice to the Delhi Police chief concerning an alleged assault on a female journalist during a student protest at Delhi University. The journalist reported being targeted for her caste. A detailed report is expected from the police within two weeks.

Devdiscourse News Desk | New Delhi | India

Updated: 20-02-2026 18:51 IST | Created: 20-02-2026 18:51 IST

The National Human Rights Commission (NHRC) announced it has sent a notice to Delhi's Police Commissioner regarding a reported assault on a female journalist at a student protest at Delhi University. The incident allegedly occurred earlier this month on February 13.

According to media reports, the journalist was on assignment covering a student protest against the UGC regulations. She was allegedly physically and sexually assaulted by a mob after her caste was identified during the event in the university's North Campus.

The NHRC has requested an extensive report from the police within two weeks to address these serious allegations of human rights violations. The journalist managed to escape with the assistance of faculty members and female police officers.

(With inputs from agencies.)

Source: https://lawtrend.in/allahabad-hct-awards-%E2%82%B910-lakh-compensation-for-prisoners-suicide-directs-state-to-frame-guidelines-for-custodial-deaths-akin-to-motor-vehicles-act/

Allahabad HCt Awards ₹10 Lakh Compensation for Prisoner's Suicide; Directs State to Frame Guidelines for Custodial Deaths Akin to Motor Vehicles Act

February 20, 2026
Judgements
By Law Trend

The High Court of Judicature at Allahabad, Lucknow Bench, has directed the State of Uttar Pradesh to pay ₹10 lakh as compensation to the mother of a minor who died by suicide in judicial custody. The Court held the State absolutely liable for the unnatural death and directed the government to frame guidelines for determining compensation in custodial death cases using a multiplier method similar to the Motor Vehicles Act, 1988.

Background of the Case

The petitioner's minor son, Sukhvinder, was arrested on February 7, 2024, in execution of a warrant related to a 2016 criminal case registered under the Protection of Children from Sexual Offences (POCSO) Act and the Indian Penal Code (IPC). He was subsequently detained in District Prison Pilibhit.

On February 20, 2024, the petitioner was informed by prison authorities that her son had died in custody. The panchnama and post-mortem reports concluded that the cause of death was "asphyxia due to antimortem hanging," indicating suicide by hanging from a toilet ventilator, with no external injuries found. Following an inquest report by the Judicial Magistrate under Section 176 CrPC (corresponding to Section 196 BNSS), the National Human Rights Commission (NHRC) directed a compensation of ₹3,00,000 to the nearest family member. Aggrieved by the State's inaction and delay in releasing the compensation, the petitioner filed a writ petition seeking a writ of mandamus for adequate compensation and action against guilty officials.

Arguments of the Parties

Petitioner: The counsel for the petitioner argued that the minor was subjected to torture by prison police personnel due to the non-fulfillment of illegal demands, including a monthly extortion of ₹4,500, which ultimately led to his unnatural death. The petitioner further contended that the respondent authorities pressured the family to perform the last rites immediately and failed to disburse the promised compensation, thereby violating fundamental rights guaranteed under Articles 14 and 21 of the Constitution. To support the claim for compensation, the petitioner relied on several precedents, including Nilabati Behera v. State of Orissa, Re-Inhuman Conditions in 1382 Prisons, and Suo Motu Custodial Violence and Other Matters Relating to Prison Conditions (Meghalaya High Court).

Respondents: The State submitted that the death was a clear act of suicide with no material on record suggesting negligence, misconduct, or custodial violence by the authorities. The respondents stated that the government had already accorded approval for the NHRC-recommended ₹3,00,000 compensation. They explained that the delay in disbursement was due to the ongoing verification of the rightful next of kin and the pending receipt of budgetary allocation.

Court's Analysis

The Division Bench, comprising Justice Shekhar B. Saraf and Justice Manjive Shukla, emphasized that a custodial death casts a strict onus upon the State and demands strict constitutional scrutiny.

"Custodial torture is a calculated assault on human dignity and whenever human dignity is wounded, civilisation takes a step backwards," the Court observed. The Bench held that the State bears an absolute, non-delegable duty

to ensure the safety of prisoners.

Relying on the International Committee of the Red Cross (ICRC) guidelines and the Supreme Court's ruling in Re-Inhuman Conditions in 1382 Prisons, the Court distinguished between natural and unnatural deaths, holding that a suicide constitutes an intentional external injury and is therefore classified as an unnatural death for which the State is absolutely liable.

The Court noted that despite the absence of external injuries, the State failed to discharge its burden of proof. "The explanations offered by the respondents is neither cogent nor sufficient to displace the presumption of the death of the petitioner's son eventuated in prision," the Court stated.

To determine the Court's authority to grant relief, the Bench referred to the Supreme Court rulings in Rudul Sah v. State of Bihar and Nilabati Behera v. State of Orissa, which established monetary compensation as an appropriate public law remedy for the infringement of the fundamental right to life. The Court also cited D.K. Basu v. State of West Bengal, reiterating that the objective of such compensation is to "apply balm to the wounds and not to punish the transgressor."

While addressing the quantum of compensation, the Court examined a Meghalaya High Court judgment (Suo Motu Custodial Violence) that created age-based compensation categories. However, noting that this specific categorization had been stayed by the Supreme Court, the Bench observed that recent higher court precedents have consistently awarded ₹10 lakh for custodial deaths.

Furthermore, the Court outlined mandatory preliminary steps to be taken in all cases of custodial death, including immediate notification to the family, prompt preparation of a panchnama, mandatory video recording of the post-mortem, an immediate judicial inquest, and the prompt payment of initial NHRC-fixed compensation.

Decision

Allowing the writ petition, the High Court directed the respondents to pay a compensation of ₹10,00,000 (Rupees Ten Lakhs) to the legal heirs of the deceased within a period of three weeks.

In a significant directive, the Court ordered the State Government to "frame guidelines fixing compensation by adopting relevant and cogent parameters in awarding compensation in custodial death cases akin to the multiplier method based on age, income and dependants as available under the Motor Vehicles Act, 1988."

The Court clarified that the awarded compensation is without prejudice to the petitioner's right to pursue appropriate civil or criminal proceedings against the concerned officials.

Case Title: Prema Devi v. State of U.P. Thru. its Prin. Secy. Home Deptt. Lko. and 5 others

Case Number: WRIT-C No. 579 of 2025

News9Live, Online News, 21/02/2026

Source: https://www.news9live.com/india/mid-day-meal-row-in-mahoba-nhrc-takes-cognisance-of-diluted-milk-incident-seeks-probe-2933654

Mid-day meal row in Mahoba: NHRC takes cognisance of diluted milk video, seeks action-taken report in 2 weeks

The incident, where children were served water mixed with minimal milk, sparked outrage and led to the head teacher's suspension. NHRC action highlights violations of children's fundamental rights to nutrition, demanding accountability and an Action Taken Report from Mahoba authorities within two weeks.

Tirtho Banerjee Updated On: 20 Feb 2026 12:48:PM

New Delhi: The National Human Rights Commission (NHRC) has taken cognisance of a video showing a litre of milk being mixed in a bucket of water for a mid-day meal at a government school in Uttar Pradesh's Mahoba. The rights body has issued a notice directing the District Magistrate of Mahoba to carry out an inquiry into the matter. It has also said that an Action Taken Report should be submitted within two weeks.

What the notice said

The notice said that the complainant alleged that in a government school in Mahoba district, children under the Mid-Day Meal (MDM) scheme are being served highly diluted milk, where only two packets of milk are reportedly are mixed into a full bucket of water and distributed to students. The notice added that the complainant further says that such a practice amounts to negligence and violates children's fundamental rights to health, dignity and proper nutrition, defeating the objective of the welfare scheme. The complainant sought the intervention of the Commission and requested for an inquiry so that action is taken against the guilty officers and such an incident is not repeated.

The notice pointed out that the NHRC has taken cognizance of the matter under section 12 of the Protection of Human Rights Act, 1993 and directed that the Action Taken Report be submitted within two weeks.

As per the MDM scheme norms, each child needs to be given 200 ml of locally available loose milk or packaged milk along with the freshly cooked meal.

Earlier, after the video the practice went viral, the education department suspended the school's head teacher, Monika Soni, who was in charge of the mid-day meal programme.

Basic Shiksha Adhikari, Mahoba, Rahul Mishra, reportedly said a probe by the block education officer found that children were given the same milk which was mixed with water. "We have suspended the head teacher and a detailed probe is underway." he said.

What did the video show

A video purportedly showed two half-litre milk packets being mixed into a large bucket of water in the presence of the teacher in charge. It went viral on social media. The video showed a cook mixing water to the milk. The diluted milk was meant to be distributed to the students.

The video sparked online fury and sarcasm. One user said on X: "Doodho nahaao, phulo phalo — looks like the blessing has taken an innovative turn: two 500 ml packets of milk poured in a bucket of water. Truly, dilution has reached this level in the state."

"Buffalo milk is so thick that it could cause stomach cramps in children. Therefore, this solid step was taken. Milk was mixed with water. Hail the mid-day meal, hail the nutrition scheme," another user wrote.

Earlier incidents

However, instance of irregularities in mid-day meals have been reported in the past as well. In October 2021, five litres of water were reportedly mixed with two litres of milk at a government school in Meerut. In November 2019, a video had surfaced from a Sonbhadra school showing a cook mixing one litre milk in a bucket of water to be

served to around 81 students. In August 2019, a viral video showed a woman distributing rotis and salt as a mid-day meal to children at a primary school in Mirzapur.

Source: https://indiaeducationdiary.in/nhrc-india-takes-suo-motu-cognizance-of-the-reported-physical-and-sexual-assault-on-a-journalist-covering-students-protest-in-the-north-campus-of-delhi-university/

NHRC, India takes suo motu cognizance of the reported physical and sexual assault on a journalist covering students' protest in the North Campus of Delhi University

By iednewsdesk | February 20, 2026

The National Human Rights Commission (NHRC), India has taken suo motu cognizance of a media report that a woman journalist was subjected to physical and sexual assault by a mob while she was on a professional assignment to cover a students' protest against the UGC regulations in the North Campus of Delhi University on 13th February 2026. Reportedly, the protesters, after identifying the journalist's caste, began assaulting her and some also threatened to parade her naked before she lost consciousness.

The CommissIon has observed that the contents of the news report, if true, raise a serious issue of violation of the human rights of the victim. Therefore, it has issued a notice to the Delhi Police Commissioner, calling for a detailed report on the matter within two Weeks.

According to the media report, carried on 14th February 2026, the victim journalist has alleged that she was specifically targeted because of her caste. She escaped her ordeal with the help of some faculty and women police personnel.

Source: https://orissadiary.com/odisha-cm-mohan-charan-majhi-questions-previous-govt-over-mandi-infrastructure-and-storage-for-farmers/

Odisha CM Mohan Charan Majhi Questions Previous Govt Over Mandi Infrastructure and Storage for Farmers

By: Suparjya Swain
Date: February 20, 2026
Bhubaneswar: Odisha Chief Minister Mohan Charan Majhi raised concerns over the development of mandi infrastructure and storage facilities for farmers during proceedings in the State Assembly.
He questioned whether 24 model mandis had been established over the past 24 years, stating that those responsible should come forward to respond. The Chief Minister further asked about the storage arrangements that were created during the previous tenure and what concrete plans had been implemented for the welfare of farmers.
He noted that had an adequate number of warehouses and storage facilities been constructed at the time, the current challenges faced by farmers could have been avoided.

Hans India, Online News, 21/02/2026

Source: https://www.thehansindia.com/news/national/surajkund-fair-tragedy-compromising-essential-elements-quite-unfair-1050281

Surajkund fair tragedy: Compromising essential elements 'quite unfair'

Created On: 20 Feb 2026 2:19 PM IST
By The Hans India

Taking cognisance of the deadly swing collapse incident and "systemic deficiencies" observed at the recently concluded Surajkund International Crafts Mela, the Haryana Human Rights Commission said that no fair, or large public event will be allowed without certification of a multidisciplinary technical committee.

The commission has also called on state government and all concerned authorities adopt a zero-tolerance approach towards compromise on public safety at mass gatherings.

The accident at the mela in Surajkund in Faridabad district on February 7 occurred when the high-speed pendulum ride, carrying about 19 people, tilted and crashed onto the ground. Inspector Jagdish Prasad (59), who was on duty at the venue, died while trying to rescue those trapped. Twelve others sustained injuries in the collapse. The commission, comprising Chairperson Justice Lalit Batra and members Kuldip Jain and Deep Bhatia, in an order dated February 12, called for detailed reports from the concerned authorities.

Taking suo motu cognisance of a media report about the swing collapse incident and the "systemic deficencies", which the HHRC observed at the mela during a visit, the commission said that no fair, festival or large public event shall be permitted to commence without prior certification of a multidisciplinary technical committee, comprising structural engineers, electrical safety experts, fire officers and disaster management officials. Mandatory third-party safety audits of all amusement rides, gates, stalls and temporary structures shall be conducted before formal inauguration and at regular intervals during the event.

Dedicated emergency response teams, ambulances, fire tenders, first-aid centres and trained rescue personnel must be deployed at strategic locations, the commission noted. A "fair (mela) must be fair in all perspectives," meaning that, along with cultural celebration and economic activity, equal emphasis must be placed on safety, accessibility, accountability and human dignity, the commission observed. Any fair that compromises on these essentials becomes, in effect, "quite unfair" to the public, it noted. Assistant Registrar, HHRC, Dr Puneet Arora, said that the commission has also sought detailed reports from the authorities.

Source: https://www.livelaw.in/amp/high-court/allahabad-high-court/allahabad-high-court-custodial-death-prisoner-suicide-absolute-state-liability-10-lakh-compensation-523984

Custodial Death | Prisoner Suicide Attracts Absolute State Liability: Allahabad High Court Awards ₹10 Lakh Compensation

By - Sparsh Upadhyay
Update: 2026-02-20 13:04 GMT

The Allahabad High Court (Lucknow Bench) recently held that the State is absolutely liable for the unnatural death of a prisoner in its custody, even if the death is a patently unnatural suicide.

A Bench of Justice Shekhar B Saraf and Justice Manjive Shukla ruled that the right to life and human dignity guaranteed under Article 21 of the Constitution of India is an intrinsic, inviolable and omnipresent right extended even to an individual who is illegally arrested and detained by the State.

The bench thus allowed a writ petition filed by one Prema Devi, seeking compensation for the unnatural death of her minor son in District Prison Pilibhit.

While directing the respondents to pay compensation of Rupees Ten Lacs to the legal heirs of the deceased within a period of three weeks, the bench also asked the UP Government to frame guidelines fixing compensation.

It added that the government must adopt relevant and cogent parameters for awarding compensation in custodial death cases, akin to the multiplier method based on age, income, and dependents, as available under the Motor Vehicles Act, 1988.

Briefly put, the petitioner's son, an undertrial in a POCSO case, had died by suicide on February 20, 2024. He was found hanging from the ventilator of a prison toilet.

The National Human Rights Commission (NHRC) earlier recommended a compensation of ₹3,00,000/-. However, due to the inaction of the authorities, the same was not paid and hence, the petitioner approached the High Court.

It was categorically claimed that the deceased was subjected to torture by the police personnel due to non-fulfilment of illegal money demands for relief from such torture, which ultimately resulted in his unnatural death.

On the other hand, the state argued that the deceased died by hanging himself. It was contended that the incident was an act of suicide and there was no material on record to suggest any negligence, misconduct or involvement on the part of the respondent authorities.

It was further submitted that once the identification process is complete and the requisite budgetary allocation is received from the Government, the approved compensation shall be released in accordance with the law.

The bench, however, rejected the State's endeavour to evade responsibility as it observed that custodial death depicts one of the most serious challenges to the protection of fundamental rights within the Indian Justice System.

Justice Saraf, writing for the bench, stated that it is 'flabbergasting' to note that there is no express mandate in our Indian Constitution for the grant of compensation for unlawful detention or custodial death.

The court added that if the death in custody occurs naturally, then the State cannot be faulted with it, but if the death is caused unnaturally, then the State is absolutely liable for its act/omission which resulted in the death of an individual.

The Allahabad HC also relied on the Supreme Court's landmark judgment in Rudul Sah v. State of Bihar, wherein it was observed that refusing to pass an order of compensation for the deprivation of fundamental rights would be doing mere lip-service to the right to liberty.

The Court also took into account the Supreme Court's rulings in Nilabati Behera v. State of Orissa and D.K. Basu v. State of West Bengal, wherein it was noted that monetary amends are an appropriate and effective remedy based on the principle of strict liability, to which the defence of sovereign immunity is unavailable.

Notably, while deciding the quantum of compensation, the Court examined a Meghalaya High Court judgment (Suo Motu Custodial Violence) which categorised compensation based on the victim's age.

However, the Division Bench refused to follow it as an authoritative precedent, observing that the said judgment had been stayed by the Supreme Court in The State of Meghalaya Vs. Killing Jana.

Against this backdrop, the Court noted from the undisputed records that the deceased was in the custody of the State and had committed suicide.

The bench said that while there may have been circumstances surrounding him which drove him to take such an extreme step, the State was, however, absolutely liable for the unnatural death of the deceased.

"...an amplified duty is cast upon the State for the death of a prisoner in custody of police without any exception. No State can shirk its duties and responsibilities for providing better facilities to prisoners. Accordingly the case of custodial death is made out in the present case", the bench remarked.

In view of this, the Court concluded that it was a clear infringement of constitutional protections, warranting intervention under Article 226 of the Constitution

Consequently, the Court allowed the writ petition and directed the State to pay ₹10,00,000 as compensation to the legal heirs within three weeks.

Going a step further to institute systemic reform, the Court mandated four preliminary steps to be strictly followed in all future cases of custodial death:

A. The family members of the deceased must be informed immediately by the jail authoritiees about the death of the deceased. A panchnama with independent panchas shall be prepared immediately on the spot in accordance with Section 174 CrPC (corresponding Section 194 BNSS) without any delay.

B. A post mortem examination must be conducted promptly mentioning the cause of death without any delay. The video recording of the post mortem examination in case of custodial death of the deceased must be mandatorily carried out.

C. An inquest report by the judicial magistrate concerned must be submitted in accordance with Section 176 CrPC (corresponding Section 196 BNSS) immediately after considering all the witnesses, post mortem report and panchnama.

D. The monetary compensation in order to provide solace to the next of kin of the deceased in custody must be paid as fixed by National Human Rights Commission after considering the peculiar facts and circumstances of the individual custodial death case

Case title - Prema Devi vs. State of U.P. Thru. its Prin. Secy. Home Deptt. Lko. and 5 others 2026 LiveLaw (AB) 91

Case citation : 2026 LiveLaw (AB) 91

Source: https://www.barandbench.com/amp/story/news/allahabad-high-court-orders-up-government-to-pay-10-lakh-to-family-of-minor-who-died-by-suicide-in-jail

Allahabad High Court orders UP government to pay ₹10 lakh to family of minor who died by suicide in jail

The Court also directed the State government to frame guidelines for payment of compensation in custodial death cases.

Bar & Bench

Published: 20th Feb, 2026 at 6:58 PM

The Allahabad High Court on Friday directed the Uttar Pradesh government to pay a compensation of ₹10 lakh to the legal heirs of a minor, who died by suicide inside the Pilibhit district jail in 2024.

A Division Bench of Justice Shekhar B Saraf and Justice Manjive Shukla opined that there may have been some "circumstances" that drove the minor to take such extreme step but the State was absolutely liable for his unnatural death inside inside the jail.

No State can shirk its duties and responsibilities for providing better facilities to prisoners, the Court said while declaring the minor's suicide to be a case of custodial death.

The Bench noted that the Supreme Court has categorically held that a suicide inside a prison would be an unnatural death for which liability would squarely fall upon the State.

"This Court finds that the death of the deceased occurred while in custody and control of the State authorities, and that the material placed on record unmistakably establishes a violation of the fundamental rights guaranteed under Article 21 of the Constitution of India," it held.

The minor was facing rape charges in a 2016 case under provisions of the Indian Penal Code (IPC) and Protection of Children under Sexual Offences (POCSO) Act. He had undergone imprisonment of about three years and ten months before he was granted bail in February 2022.

However, he was arrested on February 7, 2024, after he failed to appear before the trial court. On February 20, 2024, he hanged himself inside the prison. A magisterial inquiry later confirmed the cause of death and observed that there was no information regarding any harassment or instigation by jail authorities.

National Human Rights Commission in 2024 ordered a compensation of ₹3 lakh to the family of the minor. However, after the State failed to pay the amount, the minor's mother moved the High Court.

It was alleged that the minor was subjected to torture by police in jail due to non-payment of illegal demands including a monthly payment of ₹4,500.

However, the State denied the allegations and also said that minor had died by hanging himself. It was argued that there was no involvement of authorities in his death.

However, the Court ruled that the State was absolutely liable for unnatural deaths inside prisons.

"The explanations offered by the respondents is neither cogent nor sufficient to displace the presumption of the death of the petitioner’s son eventuated in prision. Accordingly, the onus which squarely lay upon the State to account for the circumstances leading to the death, has not been satisfactorily discharged. The contention of the State that the death was due to suicide and was not an unnatural death does not hold water as has been categorically demonstrated by the judgments as discussed above," the Bench said.

The Court also expressed surprise that Indian law has no express mandate for grant of compensation for unlawful detention or custodial death.

"India has ratified to the International Covenant in Civil and Political Rights, 1966 wherein Article 9(5) states that “Anyone who has been the victim of unlawful arrest or detention shall have an enforceable right to

compensation”. In consistence with the above ratification, India owes its obligation to the international community. Furthermore, the Law Commission of India, in its 273rd report on implementation of United Nations Convention Against Torture, has observed custodial violence marked by weak accountability, lack of transparency and institutional protection of errant officials," the Bench said.

Thus, it directed the State government to frame guidelines for payment of compensation in custodial death cases, similar "to the multiplier method based on age, income and dependants as available under the Motor Vehicles Act, 1988."

The Court ordered the State to pay the compensation of ₹10 lakh to the minor's family within three weeks,.

It also clarified that the direction shall be without prejudice to the right of the legal heirs to pursue appropriate civil or criminal proceedings against the officials concerned.

Advocates Rama Kant Dixit and Uday Kumar represented the petitioner.

Source: https://www.aninews.in/news/national/politics/commission-practice-exists-must-be-stopped-karnataka-pwd-minister-satish-jarkiholi20260220142735/?amp=1

Commission practice exists, must be stopped: Karnataka PWD Minister Satish Jarkiholi

ANI | Updated: Feb 20, 2026 14:27 IST

Bengaluru (Karnataka) [India], February 20 (ANI): Karnataka PWD Minister Satish Jarkiholi said commission practices in government departments have existed over time and called for action to end them amid allegations and protests by contractors.

Addressing a press conference on Friday, Jarkiholi said, "It was there yesterday, it is there today, and it will be there tomorrow. It's difficult to figure out at what level it's happening. Someone is on one side, someone is on the other... It's there today, and it will be there tomorrow. We need to put a stop to this."

The remarks come against the backdrop of protests announced by the Karnataka State Contractors Association (KSCA) over pending bills. The association had called for a strike at Freedom Park in Bengaluru, alleging that the government has arrears of about Rs 37,000 crore from various departments for the period between 2022-23 and 2025-26.

The KSCA said it has held multiple meetings with Chief Minister Siddaramaiah, ministers and government secretaries, but claimed that no resolution has been reached. The association alleged that scheduled meetings were postponed without reason and that representations to the Public Works Minister and Deputy Chief Minister DK Shivakumar did not yield results. It has demanded immediate clearance of outstanding bills, maintenance of seniority and release of funds in one instalment.

Meanwhile, Karnataka BJP leader R Ashok alleged irregularities in the handling of contracts. "On the contractor issue, some ministers have become package ministers. KKRDB has given many jobs to Andhra people. Telangana is getting better after the Congress government came. The contractors there and the ministers here have been match-fixing," he said.

The KSCA has urged contractors across districts to stop ongoing works and participate in the protest, stating that office bearers are touring districts to mobilise support. The issue has triggered a political exchange between the ruling Congress and the opposition BJP. (ANI)

Hindustan Gazette, Online News, 21/02/2026

Source: https://thehindustangazette.com/national/new-delhi/chhattisgarh-muslim-group-seeks-action-over-communal-incidents-targeting-minority-community-43879

Chhattisgarh: Muslim Group Seeks Action Over Communal Incidents Targeting Minority Community

By Waquar Hasan | February 20, 2026

NEW DELHI: A Muslim organisation, the Raza Unity Foundation, has called for a fair investigation and strict legal action following a series of recent incidents in which members of the Muslim community were allegedly targeted in Chhattisgarh.

On Thursday, members of the Foundation submitted a memorandum to local administrations in several districts, including Korba, Surajpur, Raipur, Bijapur, Khairagarh, Koriya and Durg. The memorandum was addressed to the Governor of Chhattisgarh, Chief Minister Vishnu Deo Sai, the Chhattisgarh Minority Commission, the National Commission for Minorities, the National Human Rights Commission (NHRC), and the Chhattisgarh Police headquarters in Raipur.

“It is respectfully submitted that recently in Chhattisgarh State, some serious and condemnable incidents related to the minority community have come to light, due to which an atmosphere of fear, insecurity, and social tension has arisen in the state,” the memorandum stated, a copy of which The Hindustan Gazette has reviewed.

The Foundation cited multiple incidents across the state.

In Dutkaiya village of Gariaband district on February 1, a mob allegedly vandalised and set fire to more than half a dozen houses owned by members of the Muslim community. At least seven police personnel were reportedly injured while shielding over two dozen people, including women and children, from a mob numbering in the hundreds for several hours.

In another incident, a Muslim vendor was allegedly assaulted and abused by a man identified as Ajay Tiwari after he checked the vendor’s identity card. A video circulating on social media purportedly shows the accused saying that “the vendor is a Pathan and he sells after spitting into their products.” An FIR was registered, and the accused was arrested.

In Devbaloda-Charoda in Durg district, during a Mahashivratri fair, incidents were reported involving Muslim traders allegedly being targeted. According to the memorandum, they were abused with religious slurs and prevented from conducting business after being asked to produce Aadhaar cards. Acting on a complaint by Mohammad Ismail, Bhilai police registered a case against Bajrang Dal leader Pradeep Sinha and several others.

A two-day fair had been organised in Devbaloda-Charoda for Mahashivratri. On February 16, Bajrang Dal workers allegedly accused a Muslim trader of concealing his identity to conduct business. The memorandum states that Muslim shopkeepers at the fair were misbehaved with, insulted in the name of religion, and subjected to vulgar comments.

In another case in Durg district, hate speeches were allegedly delivered following a dispute over the burial of a Muslim woman in Janjgiri village, where only four Muslim families reside. The village does not have a designated Muslim burial ground. The families had sought permission to bury the deceased on a piece of land, but Hindu organisations reportedly objected.

“The above incidents are related to social harmony, law and order, and the rights to equality, security, and freedom of religion granted by the Constitution,” the Foundation said in the memorandum.

The organisation has demanded a high-level, impartial inquiry into the incidents, strict legal action against those

responsible, compensation and security for the affected families, and administrative measures to prevent recurrence. It also called for meetings to be convened to maintain communal harmony across the state.

ANI, Online News, 21/02/2026

Source: https://www.aninews.in/news/national/general-news/nhrc-takes-suo-motu-cognizance-of-assault-on-journalist-covering-du-students-protest-in-north-campus20260220193842/?amp=1

NHRC takes suo motu cognizance of assault on journalist covering DU students' protest in North Campus

ANI | Updated: Feb 20, 2026 19:38 IST

New Delhi [India] February 20 (ANI): The National Human Rights Commission (NHRC) on Friday took suo motu cognizance of a media report alleging that a woman journalist was subjected to physical and sexual assault by a mob while she was on a professional assignment to cover a students' protest against the UGC regulations in the North Campus of Delhi University on February 13.

According to reports, the protesters, after identifying the journalist's caste, allegedly began assaulting her, and some reportedly threatened to parade her naked before she lost consciousness.

The Commission has observed that the contents of the news report, if true, raise a serious issue of violation of the human rights of the victim. Therefore, it has issued a notice to the Delhi Police Commissioner, calling for a detailed report on the matter within two Weeks.

According to the media report, carried on February 14, the victim journalist has alleged that she was specifically targeted because of her caste. She escaped her ordeal with the help of some faculty and women police personnel.

Further, on February 16, the NHRC issued a notice to Deputy Commissioner of Police (DCP) of North Delhi and the Vice Chancellor of Delhi University regarding the recent incident where a female journalist and content creator was allegedly assaulted by a mob at Delhi University during a UGC protest, directing them to make an inquiry into the case and submit an Action Taken Report within two weeks.

The notice detailed the allegations made by the complainant, stating, "The complainant alleged that a woman journalist and content creator was violently assaulted by a mob while she was covering a protest in support of UGC at a Delhi University's North Campus on 13.02.2026. The complainant further alleged that the attackers targeted her on the basis of her caste identity, verbally abused her, and physically assaulted/ attacked her, threatened her with violence, and attempted to outrage her."

"The complainant also alleged that the incident amounts to caste-based violence, an attack on the freedom of the press, and a serious violation of her fundamental rights to life, dignity, and personal security. The complainant sought theintervention of the Commission in the matter and requested an impartial investigation, action against the culprits/accused, security/safety, legal aid and compensation to the victim," the letter reads.

It added that Prima Facie the allegations seem to be violations of the human rights of the victim.

As per the letter, the Bench of the National Human Rights Commission, which is presided over by Priyank Kanoong, Member, took cognizance u/s 12 of the Protection of Human Rights Act, 1993, in the matter.

"The Registry is directed to issue a notice to the DCP, North Delhi and the Vice Chancellor, Delhi University, with directions to get the allegations made in the complaint inquired into and to submit an Action Taken Report within two weeks for perusal of the Commission," the NHRC stated in the notice. (ANI)

Source: https://www.newsdrum.in/national/nhrc-seeks-delhi-police-commissioners-response-on-attack-on-journalist-on-du-campus-11140284

NHRC seeks Delhi Police commissioner's response on 'attack' on 'journalist' on DU campus

NewsDrum Desk | 20 Feb 2026 18:50 IST

New Delhi, Feb 20 (PTI) The NHRC on Friday said it had issued a notice to the Delhi Police chief in connection with the alleged assault on a "woman journalist" at a student protest on the Delhi University campus earlier this month.

The National Human Rights Commission said it had sought a detailed report from the police commissioner within two weeks.

The NHRC has "taken suo motu cognisance of a media report that a woman journalist was subjected to physical and sexual assault by a mob while she was on a professional assignment to cover a students' protest against the UGC regulations in the North Campus of the Delhi University on February 13," it said, citing a news report.

The protesters, after identifying the journalist's caste, began "assaulting" her, and some also threatened to "parade her naked before she lost consciousness," the statement said.

The commission observed that the content of the news report, if true, raises a serious issue of violation of the human rights of the woman.

According to the report, carried on February 14, the "journalist has alleged that she was specifically targeted because of her caste. She escaped her ordeal with the help of some faculty and women police personnel," it said.

PTI KND VN VN

Source: https://www.jagran.com/delhi/new-delhi-city-nhrc-notice-to-delhi-police-on-du-journalist-harassment-case-40149150.html?utm_source=article_detail&utm_medium=CRE&utm_campaign=latestnews_CRE

DU रूचि तिवारी मामले में नया मोड़, एनएचआरसी ने दिल्ली पुलिस आयुक्त को नोटिस भेज दो सप्ताह में मांगा जवाब

By Ritika Mishra Edited By: Neeraj Tiwari
Updated: Sat, 21 Feb 2026 02:04 AM (IST)

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने दिल्ली विश्वविद्यालय में एक महिला पत्रकार के साथ मारपीट और यौन उत्पीड़न मामले का स्वतः संज्ञान लिया है। आयोग ने दिल्ली पुलिस आयुक्त को नोटिस जारी कर दो सप्ताह में विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। यह घटना 13 फरवरी की है।

HighLights

एनएचआरसी ने डीयू पत्रकार उत्पीड़न मामले का स्वतः संज्ञान लिया।
दिल्ली पुलिस आयुक्त को दो सप्ताह में रिपोर्ट देने का नोटिस।
जाति के आधार पर पत्रकार को निशाना बनाने का आरोप।

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) के नार्थ कैंपस में छात्र प्रदर्शन कवर करने गई महिला पत्रकार रूचि तिवारी से मारपीट और यौन उत्पीड़न के मामले का स्वत संज्ञान लिया है। आयोग ने दिल्ली पुलिस आयुक्त को नोटिस जारी कर दो सप्ताह में विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।

ये घटना 13 फरवरी की है जब दिल्ली विश्वविद्यालय नार्थ कैंपस में यूजीसी नियमों के विरोध में प्रदर्शन चल रहा था। प्रदर्शन की रिपोर्टिंग करने पहुंची महिला पत्रकार को भीड़ ने घेर लिया और उसके साथ अभद्र व्यवहार किया था।

मीडिया रिपोर्ट के हवाले से आयोग ने कहा कि प्रदर्शनकारियों ने पत्रकार की जाति पहचानने के बाद उसे निशाना बनाया। आरोप है कि भीड़ ने उसके साथ मारपीट की, यौन उत्पीड़न किया व उसे निर्वस्त्र घुमाने की धमकी भी दी। हमले के दौरान पत्रकार बेहोश हो गई थी। बाद में कुछ शिक्षकों और मौके पर तैनात महिला पुलिसकर्मियों के हस्तक्षेप से उसे सुरक्षित बाहर निकाला गया था।

आयोग ने कहा है कि यदि समाचार रिपोर्ट में लगाए गए आरोप सही साबित होते हैं तो यह न केवल एक महिला की गरिमा पर हमला है बल्कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और मीडिया की स्वतंत्र कार्यप्रणाली पर भी गंभीर प्रश्न खड़े करता है। एनएचआरसी ने दिल्ली पुलिस से अब तक दर्ज एफआइआर, आरोपितों की पहचान, गिरफ्तारी की स्थिति, पीड़िता की सुरक्षा और जांच की प्रगति से जुड़ी विस्तृत जानकारी मांगी है।

पीड़िता पत्रकार ने आरोप लगाया है कि उसे पेशेवर दायित्व निभाने के दौरान उसकी जातिगत पहचान के आधार पर निशाना बनाया गया। आयोग ने स्पष्ट किया है कि पुलिस रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद मामले की समीक्षा कर आगे की कार्रवाई, आवश्यक सिफारिशें और निर्देश जारी किए जाएंगे।

Jansatta, Online News, 21/02/2026

Source: https://www.jansatta.com/national/du-ruchi-tiwari-case-nhrc-issued-notice-delhi-police-commissioner/4418324/

डीयू रुचि तिवारी मामला: NHRC ने दिल्ली पुलिस आयुक्त को जारी किया नोटिस, दो हफ्ते में मांगी रिपोर्ट

Vivek Awasthi February 20, 2026

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने एक मीडिया रिपोर्ट का स्वतः संज्ञान लिया है। जिसमें कहा गया है कि 13 फरवरी 2026 को दिल्ली विश्वविद्यालय के नॉर्थ कैंपस में यूजीसी नियमों के खिलाफ छात्रों के विरोध प्रदर्शन को कवर करने के दौरान एक महिला पत्रकार के साथ भीड़ ने मारपीट की और यौन उत्पीड़न किया।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, प्रदर्शनकारियों ने पत्रकार की जाति का पता लगाकर उस पर हमला किया और कुछ ने उसे नग्न अवस्था में घुमाने की धमकी भी दी। जिसके बाद वह बेहोश हो गई।

आयोग ने पाया है कि यदि समाचार रिपोर्ट में दी गई जानकारी सही है, तो यह पीड़िता के मानवाधिकारों के उल्लंघन का गंभीर मुद्दा उठाती है। इसलिए, आयोग ने दिल्ली पुलिस आयुक्त को नोटिस जारी कर दो सप्ताह के भीतर इस मामले पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। हालांकि, आयोग ने पत्रकार का नाम नहीं लिया है।

The National Human Rights Commission (NHRC), India has taken suo motu cognizance of a media report that a woman journalist was subjected to physical and sexual assault by a mob while she was on a professional assignment to cover a students' protest against the UGC regulations in...

— ANI (@ANI) February 20, 2026

14 फरवरी 2026 को प्रकाशित मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, पीड़ित पत्रकार ने आरोप लगाया है कि उसे विशेष रूप से उसकी जाति के कारण निशाना बनाया गया था। वह कुछ शिक्षकों और महिला पुलिसकर्मियों की मदद से इस भयावह घटना से किसी तरह बच निकली।

यूट्यूबर रुचि तिवारी ने क्या कहा था?

महिला यूट्यूबर रुचि तिवारी ने इस मामले में पत्रकारों को बताया कि वह यूजीसी के नये नियमों को लागू करने की मांग को लेकर हो रहे प्रदर्शनों को कवर करने के लिए डीयू गई थीं। उनका कहना है कि उनके कुछ पुराने वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे और इस वजह से कुछ लोग पहले से ही उन्हें निशाना बना रहे थे।

महिला यूट्यूबर का आरोप है कि प्रदर्शनकारियों ने उससे उनकी जाति पूछी और फिर उस पर हमला कर दिया। रुचि तिवारी ने कहा, 'मैं विरोध प्रदर्शन को कवर करने गई थी। इससे पहले कि मैं अपना माइक निकाल पाती, मेरे पीछे खड़े एक व्यक्ति ने बार-बार मेरा नाम लेकर मुझे उकसाने की कोशिश की। जब मैंने उससे पूछा कि मामला क्या है तो उसने मेरा नाम और जाति पूछी। मैंने उसे अपना नाम बताया और पूछा कि क्या हुआ था। इसके बाद मामला और बढ़ गया।'

रुचि तिवारी ने कहा कि बहुत सारे लोगों ने उन्हें घेर लिया और हमला करने की कोशिश की। तिवारी का कहना है कि भीड़ में शामिल लोगों ने उन्हें बलात्कार की धमकी दी और कहा कि उन्हें नग्न अवस्था में घुमाया जाएगा। बता दें, यूजीसी के नए नियमों को लेकर बीते दिनों देश भर के कई राज्यों में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हो चुके हैं। यूजीसी के नए नियमों के समर्थन और विरोध में कई बार लोग आमने-सामने आ चुके हैं।

डीयू में UGC के नए नियमों को लेकर प्रदर्शन के दौरान बवाल

दिल्ली यूनिवर्सिटी में यूजीसी के नए नियमों को लेकर हुए प्रदर्शन के मामले में बड़ा विवाद हो गया है। हुआ यह है कि ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (आइसा) के कार्यकर्ता जब शुक्रवार को डीयू की आर्ट फैकल्टी में यूजीसी के नए नियमों के विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे तो इस दौरान एक महिला यूट्यूबर रुचि तिवारी ने कुछ प्रदर्शनकारियों पर उनके साथ मारपीट और छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया।

Source: https://lawtrend.in/allahabad-high-court-custodial-death-guidelines/

हिरासत में आत्महत्या: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ₹10 लाख मुआवजे का निर्देश दिया, मोटर वाहन अधिनियम की तर्ज पर गाइडलाइन बनाने को कहा

February 20, 2026 | Law Trend -Hindi
By Law Trend

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने न्यायिक हिरासत में आत्महत्या करने वाले एक नाबालिग की मां को 10 लाख रुपये का मुआवजा देने का उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश दिया है। कोर्ट ने इस अप्राकृतिक मौत के लिए राज्य को पूर्ण रूप से जवाबदेह माना और सरकार को निर्देश दिया कि वह मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के 'मल्टीप्लायर' (गुणक) फॉर्मूले की तर्ज पर हिरासत में मौत के मामलों में मुआवजा तय करने के लिए दिशा-निर्देश तैयार करे।

मामले की पृष्ठभूमि

याचिकाकर्ता के नाबालिग बेटे, सुखविंदर को 7 फरवरी, 2024 को गिरफ्तार किया गया था। यह गिरफ्तारी 2016 में यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम और भारतीय दंड संहिता (IPC) के तहत दर्ज एक आपराधिक मामले के वारंट के अनुपालन में की गई थी। इसके बाद उसे पीलीभीत जिला जेल में रखा गया था।

20 फरवरी, 2024 को जेल अधिकारियों ने याचिकाकर्ता को सूचना दी कि उनके बेटे की हिरासत में मौत हो गई है। पंचनामा और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण "फांसी के कारण दम घुटना" (asphyxia due to antimortem hanging) बताया गया, जो शौचालय के रोशनदान से लटककर आत्महत्या करने की ओर इशारा करता था। शरीर पर कोई बाहरी चोट नहीं पाई गई थी। धारा 176 CrPC (वर्तमान में धारा 196 BNSS) के तहत न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट के बाद, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने निकटतम परिजन को ₹3,00,000 के मुआवजे का निर्देश दिया। राज्य सरकार द्वारा इस मुआवजे को जारी करने में की जा रही देरी और निष्क्रियता से क्षुब्ध होकर, याचिकाकर्ता ने उचित मुआवजे और दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए रिट याचिका दायर की।

पक्षों की दलीलें

याचिकाकर्ता: याचिकाकर्ता के वकील ने दलील दी कि जेल के पुलिसकर्मियों द्वारा अवैध मांगों को पूरा न करने पर नाबालिग को यातनाएं दी गईं। इसमें प्रताड़ना से बचने के लिए ₹4,500 की मासिक वसूली की मांग शामिल थी, जिसके कारण अंततः उसकी अप्राकृतिक मौत हुई। याचिकाकर्ता ने यह भी आरोप लगाया कि अधिकारियों ने परिवार पर तुरंत अंतिम संस्कार करने का दबाव डाला और वादा किया गया मुआवजा भी नहीं दिया, जो संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 के तहत दिए गए मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। मुआवजे के दावे के समर्थन में नीलाबती बेहरा बनाम उड़ीसा राज्य, री-इनह्यूमन कंडीशंस इन 1382 प्रिज़न्स, और मेघालय हाईकोर्ट के स्वत: संज्ञान कस्टोडियल वायलेंस मामलों का हवाला दिया गया।

प्रतिवादी (राज्य): राज्य सरकार ने प्रस्तुत किया कि यह स्पष्ट रूप से आत्महत्या का मामला था और रिकॉर्ड पर ऐसा कोई सबूत नहीं है जो अधिकारियों की ओर से लापरवाही, कदाचार या हिरासत में हिंसा का संकेत देता हो। राज्य ने बताया कि सरकार NHRC द्वारा अनुशंसित ₹3,00,000 के मुआवजे को पहले ही मंजूरी दे चुकी है। भुगतान में देरी का कारण मृतक के वैध निकटतम परिजन के सत्यापन की चल रही प्रक्रिया और बजटीय आवंटन प्राप्त होना बताया गया।

कोर्ट का विश्लेषण

जस्टिस शेखर बी. सराफ और जस्टिस मंजीव शुक्ला की खंडपीठ ने इस बात पर जोर दिया कि हिरासत में मौत राज्य पर एक सख्त जिम्मेदारी डालती है और इसके लिए कड़ी संवैधानिक जांच की आवश्यकता होती है।

कोर्ट ने टिप्पणी की, "हिरासत में यातना मानवीय गरिमा पर एक सुनियोजित हमला है और जब भी मानवीय गरिमा को ठेस पहुँचती है, तो सभ्यता एक कदम पीछे चली जाती है।" पीठ ने माना कि कैदियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना राज्य का पूर्ण और अहस्तांतरणीय (non-delegable) कर्तव्य है।

इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस (ICRC) के दिशा-निर्देशों और री-इनह्यूमन कंडीशंस इन 1382 प्रिज़न्स मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भरोसा करते हुए, कोर्ट ने प्राकृतिक और अप्राकृतिक मौतों के बीच अंतर स्पष्ट किया। कोर्ट ने माना कि आत्महत्या एक जानबूझकर की गई बाहरी चोट (intentional external injury) है और इसलिए इसे एक अप्राकृतिक मौत के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा, जिसके लिए राज्य पूर्ण रूप से उत्तरदायी है।

कोर्ट ने इस बात पर गौर किया कि बाहरी चोटों की अनुपस्थिति के बावजूद, राज्य सबूत का भार (burden of proof) उठाने में विफल रहा। कोर्ट ने कहा, "प्रतिवादियों द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण न तो ठोस हैं और न ही उस धारणा को खारिज करने के लिए पर्याप्त हैं कि याचिकाकर्ता के बेटे की मृत्यु जेल में हुई।"

राहत प्रदान करने के अपने अधिकार को तय करने के लिए, पीठ ने रुदुल साह बनाम बिहार राज्य और नीलाबती बेहरा बनाम उड़ीसा राज्य में सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का संदर्भ दिया, जिसमें मौलिक अधिकार के उल्लंघन के लिए मौद्रिक मुआवजे को सार्वजनिक कानून के तहत एक उचित उपाय माना गया था। डी.के. बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य का हवाला देते हुए कोर्ट ने दोहराया कि ऐसे मुआवजे का उद्देश्य "घावों पर मरहम लगाना है न कि उल्लंघनकर्ता को दंडित करना।"

मुआवजे की राशि पर चर्चा करते हुए, कोर्ट ने मेघालय हाईकोर्ट के एक फैसले पर विचार किया जिसमें उम्र के आधार पर मुआवजे की श्रेणियां बनाई गई थीं। हालांकि, यह नोट करते हुए कि सुप्रीम कोर्ट ने उस विशिष्ट वर्गीकरण पर रोक लगा दी है, पीठ ने हाल के उच्च न्यायालयों के उन फैसलों पर भरोसा किया जिनमें हिरासत में मौत के लिए लगातार ₹10 लाख का मुआवजा दिया गया है।

इसके अलावा, कोर्ट ने हिरासत में मौत के सभी मामलों में उठाए जाने वाले अनिवार्य प्रारंभिक कदमों को रेखांकित किया, जिसमें परिवार को तत्काल सूचना देना, त्वरित पंचनामा तैयार करना, पोस्टमार्टम की अनिवार्य वीडियो रिकॉर्डिंग, तत्काल न्यायिक जांच (inquest) और NHRC द्वारा तय किए गए प्रारंभिक मुआवजे का त्वरित भुगतान शामिल है।

फैसला

रिट याचिका को स्वीकार करते हुए, हाईकोर्ट ने प्रतिवादियों को निर्देश दिया कि वे तीन सप्ताह की अवधि के भीतर मृतक के कानूनी वारिसों को ₹10,00,000 (दस लाख रुपये) का मुआवजा अदा करें।

एक महत्वपूर्ण निर्देश में, कोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया कि वह "मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के तहत उपलब्ध उम्र, आय और आश्रितों पर आधारित गुणक (multiplier) पद्धति के समान कस्टोडियल डेथ के मामलों में मुआवजा देने के लिए प्रासंगिक और ठोस मापदंडों को अपनाते हुए दिशा-निर्देश तैयार करे।"

कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि यह मुआवजा याचिकाकर्ता को संबंधित अधिकारियों के खिलाफ उचित नागरिक (civil) या आपराधिक (criminal) कार्यवाही शुरू करने के अधिकार से वंचित नहीं करेगा।

Source: https://vocaltv.in/national/nhrc-notice-delhi-police-commiphp/cid18270001.htm

महिला पत्रकार पर हमले के मामले में दिल्ली पुलिस आयुक्त को मानवाधिकार आयोग का नोटिस

By VocalTV Desk | Feb 20, 2026, 18:28 IST

नई दिल्ली, 20 फरवरी (हि.स.)। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने दिल्ली विश्वविद्यालय के उत्तरी परिसर में एक महिला पत्रकार के साथ हुई बर्बरता की घटना पर स्वतः संज्ञान लिया। आयोग ने इस मामले में दिल्ली पुलिस आयुक्त को नोटिस जारी कर दो सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है।

आयोग ने शुक्रवार को बताया कि 14 फरवरी को प्रकाशित खबरों के अनुसार यह घटना गत 13 फरवरी की है, जब एक महिला पत्रकार दिल्ली विश्वविद्यालय के नॉर्थ कैंपस में यूजीसी नियमों के खिलाफ हो रहे छात्रों के विरोध प्रदर्शन को कवर करने गई थी।

पीड़ित पत्रकार का आरोप है कि भीड़ ने उसकी जाति का पता चलने के बाद उसे विशेष रूप से निशाना बनाया। पेशेवर ड्यूटी के दौरान भीड़ ने पत्रकार के साथ शारीरिक मारपीट और यौन उत्पीड़न किया। प्रदर्शनकारियों ने पत्रकार को 'नग्न अवस्था में घुमाने' की धमकी दी, जिसके बाद वह बेहोश हो गई। पीड़िता कुछ शिक्षकों और महिला पुलिसकर्मियों की मदद से उस भयावह स्थिति से बच निकली।

हिन्दुस्थान समाचार / श्रद्धा द्विवेदी

Source: https://royalbulletin.in/delhi-ncr/delhi/human-rights-commission-notice-to-delhi-police-commissioner-in-case/article-150882

महिला पत्रकार पर हमले का मामला: NHRC ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को भेजा नोटिस, 2 हफ्ते में मांगी रिपोर्ट

By अर्चना सिंह | Online News Editor
Feb 20, 2026 08:57 PM IST

नई दिल्ली। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने दिल्ली विश्वविद्यालय के उत्तरी परिसर में एक महिला पत्रकार के साथ हुई बर्बरता की घटना पर स्वतः संज्ञान लिया। आयोग ने इस मामले में दिल्ली पुलिस आयुक्त को नोटिस जारी कर दो सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है।

आयोग ने शुक्रवार को बताया कि 14 फरवरी को प्रकाशित खबरों के अनुसार यह घटना गत 13 फरवरी की है, जब एक महिला पत्रकार दिल्ली विश्वविद्यालय के नॉर्थ कैंपस में यूजीसी नियमों के खिलाफ हो रहे छात्रों के विरोध प्रदर्शन को कवर करने गई थी।

पीड़ित पत्रकार का आरोप है कि भीड़ ने उसकी जाति का पता चलने के बाद उसे विशेष रूप से निशाना बनाया। पेशेवर ड्यूटी के दौरान भीड़ ने पत्रकार के साथ शारीरिक मारपीट और यौन उत्पीड़न किया। प्रदर्शनकारियों ने पत्रकार को 'नग्न अवस्था में घुमाने' की धमकी दी, जिसके बाद वह बेहोश हो गई। पीड़िता कुछ शिक्षकों और महिला पुलिसकर्मियों की मदद से उस भयावह स्थिति से बच निकली।

Source: https://arlivenews.com/2026/02/20/misuse-of-national-human-rights-commission-name-and-logo/

भ्रामक नामों से राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नाम का हो रहा दुरूपयोग

by Devendra Sharma | February 20, 2026

आयोग हुआ सख्त, सभी मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशकों को दिए कानूनी कारवाई के निर्देश

कई एनजीओ ने मानवाधिकार आयोग के नाम से मिलते जुलते भ्रामक नामों से पंजीकरण करा लिया है

नई दिल्ली,(एआर लाइव न्यूज)। देश भर में कई गैर सरकारी संगठनों(एनजीओ) द्वारा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नाम से मिलते जुलते भ्रामक नामों से पंजीकरण कराने के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने स्वतः संज्ञान लिया है। misuse of National Human Rights Commission name and logo

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग(एनएचआरसी) को देश भर से कई व्यक्तियों और गैर सरकारी संगठनों(एनजीओ) से मानवाधिकारों के उल्लंघन की शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। इन शिकायतों की जांच करते हुए आयोग ने पाया है कि कई गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ) ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नाम से मिलते जुलते भ्रामक नामों से अपना पंजीकरण करा लिया है। भ्रामक नामकरण से जनता को यह विश्वास होने लगता है कि ये संगठन या तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का हिस्सा हैं या फिर मानवाधिकारों से जुड़े मुद्दों पर काम करने के लिए आयोग द्वारा अधिकृत या मान्यता प्राप्त हैं। misuse of National Human Rights Commission name and logo

आमजन भ्रमित हो रहा

आयोग का मानना है कि इस तरह के भ्रामक नामों का जारी रहना जनता के विश्वास को कम कर सकता है, जनादेश के दुरुपयोग, धन के संभावित गबन और सार्वजनिक अधिकारियों के लिए एनएचआरसी जैसे वैधानिक निकाय और गैर सरकारी संगठनों के बीच अंतर करने में भ्रम पैदा कर सकता है। आयोग ने इससे पहले विभिन्न मंचों के माध्यम से अपने नाम और लोगो के दुरुपयोग पर चिंता व्यक्त की थी और संबंधित अधिकारियों को ऐसे संदिग्ध संगठनों से जुड़े लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कहा था। हालांकि,उल्लंघन के मामले लगातार उसके संज्ञान में आते रहे हैं।

नियमों का उल्लंघन कर प्राप्त किए गए पंजीकरणों को रद्द किया जाएगा

मामले की गंभीरता को देखते हुए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशकों को निर्देश दिया है कि वे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नाम का दुरुपयोग करने वाले या इससे मिलते जुलते भ्रामक नामों का उपयोग करने वाले गैर सरकारी संगठनों या व्यक्तियों की पहचान करें।

ऐसी गतिविधियों में संलिप्त पाए जाने वालों के खिलाफ दो सप्ताह के भीतर आवश्यक कानूनी कार्रवाई करने का आदेश भी दिया गया है। जिसमें नियमों का उल्लंघन कर प्राप्त किए गए पंजीकरणों को रद्द करना भी शामिल है। पंजीकरण अधिकारियों को भी सतर्क रहने और उल्लंघनकर्ताओं के विरुद्ध उचित कदम उठाने को भी कहा गया है।

कर्नाटक में हाल ही में एक मामला आयोग के सामने आया

हाल ही में,आयोग को राष्ट्रीय मानवाधिकार परिषद (एनएचआरसी) के रूप में पंजीकृत एक गैर सरकारी संगठन के बारे में पता चला, जो कथित तौर पर 2022 में दिल्ली सरकार से पंजीकृत है। इसके प्रचार सामग्री में यह दावा किया गया है कि संगठन नीति आयोग में पंजीकृत, भारत के कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय में पंजीकृत,भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत पंजीकृत और आंध्र प्रदेश मानवाधिकार परिषद संघ से संबद्ध है। संबंधित संगठन के एक विजिटिंग कार्ड पर वेंकटेश राज्य अध्यक्ष, कर्नाटक भी उल्लेखित है।

आयोग ने स्वतः संज्ञान लेते हुए कर्नाटक के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक तथा दिल्ली के मुख्य सचिव और पुलिस आयुक्त को निर्देश दिया गया है कि वे कर्नाटक में कार्यालय चलाने वाले और दिल्ली में पंजीकृत इस गैर सरकारी संगठन के खिलाफ की गई कार्रवाई के संबंध में दो सप्ताह के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

डिसक्लेमर: एआर लाइव न्यूज (AR Live News) से मिलते-जुलते नामों से रहें सावधान, उनका एआर लाइव न्यूज से कोई संबंध नहीं है। एआर लाइव न्यूज के संबंध में कोई भी बात करने के लिए पत्रकार लकी जैन (9887071584) और पत्रकार देवेन्द्र शर्मा (9672982063) ही अधिकृत हैं।

Source: https://npg.news/chhattisgarh/chhattisgarh-me-manavadhikar-se-sanchalit-ho-rahi-sansthaon-par-giregi-gaj-latest-cg-news-hindi-npg-20-02-2026-1305901

मानवाधिकार संस्थाओं पर खतरा: छत्तीसगढ़ में मानवाधिकार के नाम से चल रही संस्थाओं पर गिरेगी गाज

Anjali Vaishnav 20 फ़रवरी 2026

रायपुर।20 फरवरी 2026| छत्तीसगढ़ में बड़ी संख्या में ऐसी संस्थाएं और समिति कार्यरत हैं, जिनके नाम पर मानवाधिकार शब्द जुड़ा हुआ है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मानवाधिकार से मिलते- जुलते नामों के इस्तेमाल पर आपत्ति की है। इन संस्थाओं ने मानवाधिकार शब्द का उपयोग कर पंजीकरण भी करा लिया है। इसमें से ज्यादातर संस्थाएं मानवाधिकार के नाम पर राज्य और केंद्र सरकार से फंड भी हासिल कर रही हैं। माना जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में जांच के दौरान इस तरह की संस्थाएं बड़ी संख्या में मिलेंगी और इन पर कार्रवाई कर रिपोर्ट राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को भेज दी जाएगी।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) का मुख्य उद्देश्य मानव अधिकार के मामलों की निगरानी करना है। इस दौरान देश के नागरिकों और गैर सरकारी संगठनों द्वारा मानव अधिकार शब्द का इस्तेमाल कर दुरुपयोग करने के मामले भी आ रहे हैं। आयोग को शिकायत के साथ जानकारी भी मिली है कि कई गैरसरकारी संस्थाओं ने मानवाधिकार शब्द का उपयोग कर संस्था का नाम तय कर लिया है और इसका बाकायदा पंजीकरण भी कराकर कार्यालय खोल लिया गया है। जबकि ऐसी संस्थाओं को मानव अधिकार आयोग की ओर से किसी तरह का अधिकार नहीं दिया गया है। इन शिकायतों को मानव अधिकार आयोग ने गंभीरता से लेते हुए स्वत: संज्ञान लिया है।

दिल्ली में सामने आया मामला

आयोग के सामने ताजा मामला दिल्ली मं आया है। यहां जानकारी मिली कि दिल्ली सरकार में पंजीकृत करवा कर वर्ष 2022 से एक गैरसरकारी संस्था काम कर रही है। उस संस्था का कहना है कि उसे नीतिआयोग, कॉर्पोरेट मंत्रालय और सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय से पंजीयन मिला है। साथ ही दावा किया गया है कि वह आंध्र प्रदेश मानवाधिकार परिषद से भी संबद्ध है। इस प्रकरण को आयोग ने बहुत ही गंभीरता से लिया है और इसके बाद पूरे देश में मानव अधिकार के नाम से चल रहे गैरसरकारी संगठनों की पड़ताल कर सभी राज्यों से रिपोर्ट मांगी गई है।

आयोग ने जताई चिंता

देशभर में मानव अधिकार के उल्लंघन के मामलों की शिकायत बढ़ रही है। ऐसे में मानव अधिकार आयोग से मिलते-जुलते संगठन इसका फायदा उठा रहे हैं। गैरकानूनी रूप से मानव अधिकार के उल्लंघन के मामलों में दखल दे रहे हैं। ऐसे में इस तरह की संस्थाओं के पदाधिकारियों पर कार्रवाई करने के लिए पूर्व में ही अफसरों को दिशा- निर्देश दिए जा चुके थे।

सभी राज्यों में होगी कार्रवाई

आयोग ने मामले की गंभीरता का देखते हुए सभी प्रदेशों के मुख्य सचिव और डीजीपी को कहा है कि वह मानवाधिकार के नाम से चल रही संस्थाओं की जानकारी जुटाएं और गलत तरीके से काम कर रहे सभी संगठनों की रिपोर्ट दो सप्ताह में भेज दें। माना जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में भी ऐसी संस्थाओं की जल्द पतासाजी की जाएगी और फिर इसकी पूरी रिपोर्ट बना कर मानवाधिकार आयोग को भेज दी जाएगी। संदिग्ध और गैरकानूनी तरीके से चल रही संस्थाओं के पंजीयन भी निरस्त करने की सिफारिश की जा सकती है।

Panchjanya, Online News, 21/02/2026

Source: https://panchjanya.com/2026/02/20/459095/bharat/delhi/human-rights-commission-issues-notice-to-delhi-police-commissioner/

दिल्ली पुलिस कमिश्नर को आयोग का नोटिस

एजेंसी 20 फ़रवरी 2026

नई दिल्ली : राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने दिल्ली विश्वविद्यालय के उत्तरी परिसर में एक महिला पत्रकार के साथ हुई बर्बरता की घटना पर स्वतः संज्ञान लिया। आयोग ने इस मामले में दिल्ली पुलिस आयुक्त को नोटिस जारी कर दो सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है।

आयोग ने शुक्रवार को बताया कि 14 फरवरी को प्रकाशित खबरों के अनुसार यह घटना गत 13 फरवरी की है, जब एक महिला पत्रकार दिल्ली विश्वविद्यालय के नॉर्थ कैंपस में यूजीसी नियमों के खिलाफ हो रहे छात्रों के विरोध प्रदर्शन को कवर करने गई थी।

पीड़ित पत्रकार का आरोप है कि भीड़ ने उसकी जाति का पता चलने के बाद उसे विशेष रूप से निशाना बनाया। पेशेवर ड्यूटी के दौरान भीड़ ने पत्रकार के साथ शारीरिक मारपीट और यौन उत्पीड़न किया। प्रदर्शनकारियों ने पत्रकार को 'नग्न अवस्था में घुमाने' की धमकी दी, जिसके बाद वह बेहोश हो गई। पीड़िता कुछ शिक्षकों और महिला पुलिसकर्मियों की मदद से उस भयावह स्थिति से बच निकली।

Amar Ujala, Online News, 21/02/2026

Source: https://www.amarujala.com/uttar-pradesh/maharajganj/strict-instructions-on-child-labour-and-bonded-labour-maharajganj-news-c-227-1-sdn1035-153806-2026-02-20

Maharajganj News: बाल श्रम और बंधुआ मजदूरी पर सख्ती के निर्देश

संवाद न्यूज एजेंसी, महाराजगंज Updated Fri, 20 Feb 2026 02:50 AM IST

सिद्धार्थनगर। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के स्पेशल मॉनिटर धनंजय टिंगल ने बृहस्पतिवार को बाल श्रम और बंधुआ श्रम की स्थिति की समीक्षा की। रेस्ट हाउस में आयोजित बैठक में अधिकारियों के साथ अब तक की कार्रवाई और आगे की रणनीति तय की गई। स्पेशल मॉनिटर ने कहा कि बाल श्रम और बंधुआ मजदूरी मानवाधिकारों का गंभीर उल्लंघन हैं। ऐसे मामलों में जीरो टॉलरेंस नीति अपनाते हुए दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। साथ ही, मुक्त कराए गए बच्चों के पुनर्वास, शिक्षा और कौशल विकास पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी शिवशरणप्पा जीएन और पुलिस अधीक्षक डॉ. अभिषेक महाजन ने कहा कि बंधुआ श्रम की शिकायत पर तत्काल कार्रवाई की जाती है। सहायक श्रम आयुक्त सचिन कुमार सिंह ने बताया कि श्रमिकों का पंजीकरण कर उन्हें विभिन्न योजनाओं से जोड़ा जा रहा है। बैठक में विभागीय समन्वय मजबूत करने और प्रत्येक प्रकरण की नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया। बैठक के अंत में स्पेशल मॉनिटर ने बाल श्रम से मुक्त कराए गए तीन बच्चों और उनके परिजनों से मुलाकात कर उनकी वर्तमान स्थिति की जानकारी ली। इस अवसर पर अफसर और एनजीओ प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

Source: https://www.jagran.com/chhattisgarh/raipur-ambikapur-sdm-row-ramnaresh-ram-death-sons-seek-justice-40148086.html?utm_source=article_detail&utm_medium=CRE&utm_campaign=latestnews_CRE

अंबिकापुर में एसडीएम-साथियों की पिटाई से मृत बुजुर्ग के बेटे चेन्नई से लौटे, बोले- दोषियों को मिले सजा

By Digital Desk Edited By: Shashank Baranwal
Updated: Fri, 20 Feb 2026 07:05 AM (IST)

अंबिकापुर में एसडीएम से जुड़े विवाद में रामनरेश राम की मौत के बाद उनके बेटे चेन्नई से लौटे, जो पिता की अंतिम झलक भी नहीं देख पाए। यह घटना क्षेत्र में अवैध बॉक्साइट खनन और स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार की कमी को उजागर करती है। विधानसभा नेता प्रतिपक्ष ने मानवाधिकार आयोग से निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है, साथ ही पीड़ित परिवार को न्याय और मुआवजा दिलाने पर जोर दिया है।

HighLights

रामनरेश राम की मौत एसडीएम विवाद से जुड़ी।
बेटे चेन्नई से लौटे, अवैध खनन पर सवाल।
नेता प्रतिपक्ष ने मानवाधिकार आयोग से जांच मांगी।

जेएनएन, अंबिकापुर। कुसमी एसडीएम से जुड़े विवाद और ग्रामीण रामनरेश राम की मौत की घटना ने सामरी क्षेत्र में बाक्साइट खदानों के संचालन के बाद भी रोजगार की उपलब्धता नहीं होने को भी सामने ला दिया है। अंतिम संस्कार के बाद मृतक के बेटे संजय कुमार और किशुन चेन्नई से वापस लौटे, लेकिन उनके दिल में सबसे बड़ा दर्द इस बात का है कि वे अपने पिता की अंतिम झलक भी नहीं देख सके।

परिवार का एक अन्य बेटा सिलमन पिता के साथ ही गांव में रहता था और घटना के समय वही मौजूद था।संजय और किशुन चेन्नई के नजदीक एक मछली पालन केंद्र में मजदूरी कर परिवार का भरण-पोषण करते थे। दोनों भाइयों ने बताया कि वे मेहनत मजदूरी कर जो पैसा भेजते थे, उसी से उनके पिता रामनरेश राम खेती-बाड़ी और घर का खर्च चलाते थे।

पिता की अचानक हुई मौत ने परिवार को भावनात्मक और आर्थिक दोनों रूप से झकझोर दिया है।इस घटना ने क्षेत्र में रोजगार और संसाधनों के बंटवारे पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार, आसपास के क्षेत्र में बाक्साइट की कई खदानें संचालित हैं और वर्षों से यहां से उत्खनन व परिवहन जारी है, लेकिन स्थानीय युवाओं को पर्याप्त रोजगार नहीं मिल पा रहा है।

यही कारण है कि संजय और किशुन सहित आसपास के लगभग 20 युवा आज भी रोजी-रोटी की तलाश में दूसरे राज्यों में काम करने को मजबूर हैं। झारखंड सीमा पर बाक्साइट के अवैध उत्खनन को ही इस घटना का मूल कारण माना जा रहा है। ग्रामीण लंबे समय से अवैध उत्खनन का विरोध कर रहे थे।

आरोप है कि गांववालों को डराने-धमकाने के प्रयास में एसडीएम और उनके साथियों ने तीन ग्रामीणों की बेरहमी से पिटाई की, जिसमें गंभीर रूप से घायल रामनरेश राम की मौत हो गई। घटना के बाद पूरे इलाके में आक्रोश और शोक का माहौल है।

उच्च गुणवत्ता का बाक्साइट निकल रहा अवैध खदान से

ग्रामीणों का कहना है कि जिस अवैध खदान को लेकर विवाद हुआ, वहां से उच्च गुणवत्ता का बाक्साइट निकाला जा रहा था। सरगुजांचल के अन्य खदानों से निकलने वाला बाक्साइट पत्थर आमतौर पर लाल रंग का होता है और उसमें मिट्टी का मिश्रण अधिक रहता है, जबकि छत्तीसगढ़-झारखंड सीमा पर हंसपुर के नजदीक संचालित अवैध खदान का बाक्साइट ज्यादा चमकदार बताया जा रहा है, जिससे उसमें एल्युमिना की मात्रा अधिक होने की संभावना जताई जा रही है। इसी वजह से बाहरी प्रभावशाली लोगों की नजर इस खदान पर थी और आरोप है कि एसडीएम से जुड़े कुछ युवक भी इस धंधे से जुड़े हुए थे।

रोजगार के अवसर नहीं मिलने से बाहर जा रहे युवा

रामनरेश राम की मौत ने केवल एक परिवार का सहारा नहीं छीना, बल्कि प्रशासनिक जवाबदेही और संसाधनों पर स्थानीय अधिकार को लेकर बड़ा मुद्दा सामने लाया है। जहां एक ओर क्षेत्र की खदानों से बड़ी मात्रा में बाक्साइट बाहर भेजा जा रहा हैं, वहीं दूसरी ओर स्थानीय युवा रोजगार के लिए भटकने को मजबूर हैं। अब ग्रामीणों और सामाजिक संगठनों की मांग है कि मामले की निष्पक्ष जांच हो, दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए और क्षेत्र के संसाधनों से स्थानीय लोगों को न्याय और रोजगार दोनों मिलें।

विस नेता प्रतिपक्ष ने मानवाधिकार आयोग को लिखा पत्र

विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत ने रामनरेश राम के मौत की घटना को लेकर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से स्वतंत्र एवं विस्तृत जांच कराने की मांग की है। डॉ. महंत ने आयोग के अध्यक्ष जस्टिस वी रामासुब्रमणियन को पत्र लिखकर कहा है कि प्रशासनिक कार्रवाई के दौरान कथित रूप से अत्यधिक बल प्रयोग के कारण एक निर्दोष आदिवासी ग्रामीण की मौत हुई है। इस घटना से स्थानीय समुदाय और नागरिक समाज में आक्रोश और चिंता का माहौल है तथा प्रशासनिक जवाबदेही और मानवाधिकारों की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हुए हैं।

पत्र में उन्होंने कहा कि यदि आरोप सही पाए जाते हैं तो यह मानवाधिकारों का गंभीर उल्लंघन होगा, इसलिए निष्पक्ष और उच्चस्तरीय जांच जरूरी है। उन्होंने

आयोग से पूरे घटनाक्रम की स्वतंत्र जांच शुरू करने, जिम्मेदार अधिकारियों की पहचान करने, दोषियों के खिलाफ कानूनी एवं प्रशासनिक कार्रवाई की सिफारिश करने तथा पीड़ित परिवार को तत्काल मुआवजा और सहयोग उपलब्ध कराने की मांग की है।

इसके साथ ही घटना में प्रभावित ग्रामीणों के उचित उपचार और पुनर्वास की व्यवस्था सुनिश्चित करने का भी आग्रह किया गया है। डा महंत ने कहा कि इस मामले में त्वरित कार्रवाई से ही न्याय व्यवस्था में जनता का विश्वास कायम रहेगा।

Source: https://webvarta.com/states/uttar-pradesh/siddharthnagar-child-labour-bonded-labour-action/

सिद्धार्थनगर में बाल श्रम और बंधुआ मजदूरी पर सख्ती, मानवाधिकार आयोग के स्पेशल मॉनिटर के कड़े निर्देश | Webvarta
By Webvarta Desk | February 20, 2026

सिद्धार्थनगर, सन्दीप पाण्डेय | वेब वार्ता
उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले में बाल श्रम और बंधुआ मजदूरी के खिलाफ प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए शून्य सहनशीलता की नीति लागू करने के संकेत दिए हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के स्पेशल मॉनिटर धनंजय टिंगल के दौरे के दौरान इस दिशा में कई महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए गए।
जनपद मुख्यालय स्थित रेस्ट हाउस में आयोजित समीक्षा बैठक में जिलाधिकारी शिवशरणप्पा जीएन, पुलिस अधीक्षक डॉ. अभिषेक महाजन, मुख्य विकास अधिकारी बलराम सिंह, सहायक श्रम आयुक्त सचिन कुमार सिंह सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।
मानवाधिकार उल्लंघन पर जीरो टॉलरेंस नीति
बैठक के दौरान स्पेशल मॉनिटर ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि बाल श्रम और बंधुआ मजदूरी मानवाधिकारों का गंभीर उल्लंघन है और ऐसे मामलों में किसी भी स्तर पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा।
उन्होंने निर्देश दिया कि दोषियों के विरुद्ध कठोरतम कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए, साथ ही पीड़ित बच्चों के पुनर्वास, शिक्षा और कौशल विकास को प्राथमिकता दी जाए।
संयुक्त टीमें चला रहीं नियमित अभियान
जिलाधिकारी शिवशरणप्पा जीएन ने बताया कि श्रम विभाग, पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीमें लगातार छापेमारी अभियान चला रही हैं।
ईंट-भट्ठों, निर्माण स्थलों, ढाबों, कारखानों और अन्य संदिग्ध प्रतिष्ठानों की नियमित जांच की जा रही है, ताकि किसी भी स्तर पर बाल श्रम की गतिविधियों को रोका जा सके।
पुलिस की अपील: सूचना दें, पहचान गोपनीय रहेगी
पुलिस अधीक्षक डॉ. अभिषेक महाजन ने आम नागरिकों से अपील की कि यदि कहीं भी बाल श्रम या बंधुआ मजदूरी का मामला सामने आए, तो उसकी सूचना तत्काल प्रशासन को दें।
उन्होंने भरोसा दिलाया कि सूचना देने वालों की पहचान गोपनीय रखी जाएगी और त्वरित कार्रवाई की जाएगी।
मैदानी अधिकारियों को सक्रिय भूमिका के निर्देश
बैठक में यह भी निर्देश दिया गया कि खंड विकास अधिकारी, उपजिलाधिकारी, तहसीलदार और खंड शिक्षा अधिकारी बाल श्रम से जुड़े मामलों में सक्रिय भूमिका निभाएं।
सभी अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि अपने-अपने क्षेत्रों में निरंतर निगरानी रखें और किसी भी शिकायत को गंभीरता से लें।
एनजीओ की भूमिका पर विशेष जोर
स्पेशल मॉनिटर ने गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) से भी सक्रिय सहयोग की अपेक्षा जताई।
उन्होंने कहा कि मुक्त कराए गए बच्चों का पुनर्वास, शिक्षा और सामाजिक पुनर्स्थापन एनजीओ की मदद से और अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है, ताकि वे दोबारा श्रम में न लौटें।
मुक्त कराए गए बच्चों से की मुलाकात
बैठक के समापन के बाद स्पेशल मॉनिटर ने बाल श्रम से मुक्त कराए गए तीन बच्चों और उनके परिजनों से मुलाकात की।
उन्होंने बच्चों की वर्तमान स्थिति, शिक्षा और पारिवारिक परिस्थितियों की जानकारी ली और हर संभव सहायता का भरोसा दिलाया।
प्रशासन की प्राथमिकता: सुरक्षित बचपन
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि बच्चों का सुरक्षित बचपन, सम्मानजनक जीवन और शोषण से मुक्ति सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है।
अधिकारियों ने कहा कि इस दिशा में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
निष्कर्ष
सिद्धार्थनगर में हुई यह समीक्षा बैठक बाल श्रम और बंधुआ मजदूरी के विरुद्ध प्रशासनिक प्रतिबद्धता को दर्शाती है।
यदि निर्देशों का प्रभावी क्रियान्वयन हुआ, तो यह जिले में बाल अधिकारों की सुरक्षा की दिशा में एक मजबूत कदम साबित होगा।

Source: https://hindi.livelaw.in/amp/allahabad-highcourt/custodial-death-prisoner-suicide-attracts-absolute-state-liability-allahabad-high-court-awards-10-lakh-compensation-523992

Custodial Death | कैदी की आत्महत्या पर पूरी तरह से राज्य की ज़िम्मेदारी: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ₹10 लाख का मुआवज़ा दिया

By – Shahadat | Update: 2026-02-20 13:43 GMT

इलाहाबाद हाईकोर्ट (लखनऊ बेंच) ने हाल ही में कहा कि राज्य अपनी कस्टडी में किसी कैदी की अप्राकृतिक मौत के लिए पूरी तरह से ज़िम्मेदार है, भले ही मौत साफ़ तौर पर अप्राकृतिक आत्महत्या हो।

जस्टिस शेखर बी सराफ और जस्टिस मंजीव शुक्ला की बेंच ने फैसला सुनाया कि भारत के संविधान के आर्टिकल 21 के तहत गारंटी वाला जीवन और इंसानी गरिमा का अधिकार एक अंदरूनी, अलंघनीय और हर जगह मौजूद अधिकार है, जो उस व्यक्ति को भी दिया जाता है जिसे राज्य ने गैर-कानूनी तरीके से गिरफ्तार और हिरासत में लिया हो।

इस तरह बेंच ने प्रेमा देवी की रिट पिटीशन को मंज़ूरी दे दी, जिसमें उन्होंने पीलीभीत ज़िला जेल में अपने नाबालिग बेटे की अप्राकृतिक मौत के लिए मुआवज़े की मांग की थी।

जवाब देने वालों को तीन हफ़्ते के अंदर मृतक के कानूनी वारिसों को दस लाख रुपये का मुआवज़ा देने का निर्देश देते हुए बेंच ने यूपी सरकार से मुआवज़ा तय करने के लिए गाइडलाइन बनाने को भी कहा।

इसमें यह भी कहा गया कि सरकार को मोटर व्हीकल्स एक्ट, 1988 के तहत उपलब्ध उम्र, इनकम और डिपेंडेंट्स के आधार पर मल्टीप्लायर मेथड की तरह कस्टोडियल डेथ के मामलों में मुआवजा देने के लिए ज़रूरी और ठोस पैरामीटर अपनाने चाहिए।

संक्षेप में मामला

याचिकाकर्ता का बेटा POCSO केस में अंडरट्रायल था। वह 20 फरवरी, 2024 को सुसाइड कर गया। वह जेल के टॉयलेट के वेंटिलेटर से लटका हुआ मिला। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन (NHRC) ने पहले ₹3,00,000/- के मुआवजे की सिफारिश की थी। हालांकि, अधिकारियों के कोई कार्रवाई न करने के कारण यह पेमेंट नहीं किया गया। इसलिए याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

यह साफ तौर पर दावा किया गया कि मृतक को पुलिस वालों ने टॉर्चर किया, क्योंकि इस तरह के टॉर्चर से राहत के लिए गैर-कानूनी पैसे की मांग पूरी नहीं की गई, जिसके कारण आखिरकार उसकी अननैचुरल मौत हो गई।

दूसरी ओर, राज्य ने तर्क दिया कि मृतक ने खुद को फांसी लगाकर जान दी। यह कहा गया कि यह घटना सुसाइड थी और रिकॉर्ड में ऐसा कोई मटीरियल नहीं था जिससे पता चले कि रेस्पोंडेंट अथॉरिटीज़ की तरफ से कोई लापरवाही, गलत काम या शामिल था।

यह भी कहा गया कि एक बार पहचान का प्रोसेस पूरा हो जाने और सरकार से ज़रूरी बजट मिल जाने के बाद मंज़ूर किया गया मुआवज़ा कानून के हिसाब से जारी कर दिया जाएगा।

हालांकि, बेंच ने ज़िम्मेदारी से बचने की राज्य की कोशिश खारिज की, क्योंकि उसने कहा कि कस्टोडियल डेथ इंडियन जस्टिस सिस्टम में फंडामेंटल राइट्स की सुरक्षा के लिए सबसे गंभीर चुनौतियों में से एक है।

जस्टिस सराफ ने बेंच के लिए लिखते हुए कहा कि यह 'हैरान करने वाली' बात है कि हमारे भारतीय संविधान में गैर-कानूनी हिरासत या कस्टोडियल डेथ के लिए मुआवज़ा देने का कोई साफ़ आदेश नहीं है।

कोर्ट ने आगे कहा कि अगर कस्टडी में मौत नेचुरली होती है तो राज्य को इसके लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता। हालांकि, अगर मौत अप्राकृतिक हुई है तो राज्य अपने उस काम/चूक के लिए पूरी तरह से ज़िम्मेदार है जिसके कारण किसी व्यक्ति की मौत हुई।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रुदुल साह बनाम बिहार राज्य मामले में सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले पर भी भरोसा किया, जिसमें कहा गया कि बुनियादी अधिकारों से वंचित करने पर मुआवज़े का आदेश देने से इनकार करना आज़ादी के अधिकार के प्रति सिर्फ़ दिखावटी वादा करना होगा।

कोर्ट ने नीलाबती बेहरा बनाम उड़ीसा राज्य और डी.के. बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य में सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को भी ध्यान में रखा, जिसमें यह कहा गया कि पैसे की भरपाई स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के सिद्धांत पर आधारित एक सही और असरदार उपाय है, जिसके लिए सॉवरेन इम्यूनिटी का बचाव मौजूद नहीं है।

खास तौर पर मुआवज़े की रकम तय करते समय कोर्ट ने मेघालय हाईकोर्ट के एक फैसले (सुओ मोटो कस्टोडियल वायलेंस) की जांच की, जिसमें पीड़ित की उम्र के आधार पर मुआवज़े को कैटेगरी में बांटा गया।

हालांकि, डिवीजन बेंच ने इसे आधिकारिक मिसाल के तौर पर मानने से यह देखते हुए इनकार किया कि उस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने मेघालय राज्य बनाम किलिंग जाना में रोक लगा दी थी।

इस पृष्ठभूमि में कोर्ट ने बिना किसी विवाद वाले रिकॉर्ड से नोट किया कि मृतक राज्य की कस्टडी में था और उसने आत्महत्या कर ली थी। बेंच ने कहा कि हो सकता है कि उसके आस-पास ऐसे हालात रहे हों, जिनकी वजह से उसने इतना बड़ा कदम उठाया, लेकिन मरने वाले की अप्राकृतिक मौत के लिए राज्य पूरी

तरह से ज़िम्मेदार है।

बेंच ने कहा,

"...पुलिस की कस्टडी में किसी कैदी की मौत के लिए राज्य की ज़िम्मेदारी बढ़ जाती है। कोई भी राज्य कैदियों को बेहतर सुविधाएं देने की अपनी ज़िम्मेदारियों से बच नहीं सकता। इसलिए इस मामले में कस्टोडियल डेथ का मामला बनता है।"

इसे देखते हुए कोर्ट ने यह नतीजा निकाला कि यह संवैधानिक सुरक्षा का साफ़ उल्लंघन था, जिसके लिए संविधान के आर्टिकल 226 के तहत दखल देना ज़रूरी है।

इसलिए कोर्ट ने रिट पिटीशन मंज़ूर कर ली और राज्य को तीन हफ़्ते के अंदर कानूनी वारिसों को मुआवज़े के तौर पर ₹10,00,000 देने का निर्देश दिया।

सिस्टम में सुधार लाने के लिए एक कदम और आगे बढ़ते हुए कोर्ट ने भविष्य में कस्टोडियल डेथ के सभी मामलों में सख्ती से पालन किए जाने वाले चार शुरुआती कदम बताए:

A. जेल अधिकारियों को मृतक के परिवार वालों को मृतक की मौत के बारे में तुरंत बताना होगा। बिना किसी देरी के CrPC की धारा 174 (BNSS की धारा 194) के अनुसार, मौके पर ही इंडिपेंडेंट पंचों के साथ एक पंचनामा तैयार किया जाएगा।

B. बिना किसी देरी के मौत का कारण बताते हुए तुरंत पोस्टमॉर्टम जांच की जानी चाहिए। मृतक की कस्टोडियल डेथ के मामले में पोस्टमॉर्टम जांच की वीडियो रिकॉर्डिंग ज़रूरी तौर पर की जानी चाहिए।

C. सभी गवाहों, पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट और पंचनामा पर विचार करने के तुरंत बाद CrPC की धारा 176 (BNSS की धारा 196) के अनुसार संबंधित ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट द्वारा जांच रिपोर्ट जमा की जानी चाहिए।

D. कस्टडी में मरने वाले के परिवार वालों को सांत्वना देने के लिए नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन द्वारा तय किया गया मुआवज़ा, हर कस्टोडियल डेथ केस के खास तथ्यों और हालात पर विचार करने के बाद दिया जाना चाहिए।

Case title - Prema Devi vs. State of U.P. Thru. its Prin. Secy. Home Deptt. Lko. and 5 others 2026 LiveLaw (AB) 91

Source: https://janchowk.com/allahabad-high-court-orders-compensation-of-rs-10-lakh-in-case-of-prisoners-suicide/

कैदी की आत्महत्या के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 10 लाख का मुआवज़ा देने का निर्देश दिया

by जेपी सिंह | February 20, 2026
1 minute

इलाहाबाद हाईकोर्ट (लखनऊ बेंच) ने हाल ही में कहा कि राज्य अपनी हिरासत में किसी कैदी की अप्राकृतिक मौत के लिए पूरी तरह से ज़िम्मेदार है, भले ही मौत आत्महत्या हो।

जस्टिस शेखर बी सराफ और जस्टिस मंजीव शुक्ला की खंडपीठ ने फैसला सुनाया कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और इंसानी गरिमा का अधिकार एक मूलभूत, अलंघनीय और हर जगह मौजूद अधिकार है, जो उस व्यक्ति को भी दिया जाता है जिसे राज्य ने गैर-कानूनी तरीके से गिरफ्तार और हिरासत में लिया हो।

खंडपीठ ने प्रेमा देवी की रिट पिटीशन को मंज़ूरी दे दी, जिसमें उन्होंने पीलीभीत ज़िला जेल में अपने नाबालिग बेटे की अप्राकृतिक मौत के लिए मुआवज़े की मांग की थी। उत्तर प्रदेश सरकार को तीन हफ़्ते के अंदर मृतक के कानूनी वारिसों को दस लाख रुपये का मुआवज़ा देने का निर्देश देते हुए बेंच ने उसे से मुआवज़ा तय करने के लिए गाइडलाइन बनाने को भी कहा।

इसमें यह भी कहा गया कि सरकार को मोटर व्हीकल्स एक्ट, 1988 के तहत उपलब्ध उम्र, आय और आश्रित सदस्यों के आधार पर गुणात्मक पद्धति की तरह हिरासत में मौत के मामलों में मुआवजा देने के लिए ज़रूरी और ठोस पैमाने अपनाने चाहिए।

याचिकाकर्ता का बेटा एक पॉक्सो मामले में विचाराधीन कैदी था। वह 20 फरवरी, 2024 को जेल के शौचालय के वेंटिलेटर से लटका हुआ मिला। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने पहले ₹3,00,000/- के मुआवजे की सिफारिश की थी। हालांकि, अधिकारियों के कोई भुगतान नहीं किया। इसलिए याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

याचिकाकर्ता का आरोप था कि उनके बेटे को पुलिसकर्मियों ने टॉर्चर किया था।

दूसरी ओर, राज्य ने तर्क दिया कि मृतक ने खुद को फांसी लगाकर जान दी। यह कहा गया कि यह घटना आत्महत्या थी और रिकॉर्ड में ऐसी कोई सामग्री नहीं थी कि जिससे पता चले कि पुलिस की तरफ से कोई लापरवाही, गलत काम किया गया। यह भी कहा गया कि एक बार पहचान की प्रक्रिया पूरी हो जाने और सरकार से ज़रूरी बजट मिल जाने के बाद मंज़ूर किया गया मुआवज़ा कानून के हिसाब से जारी कर दिया जाएगा।

हालांकि, खंडपीठ ने ज़िम्मेदारी से बचने की राज्य की कोशिश खारिज की, क्योंकि उसने कहा कि हिरासत में मौत भारतीय न्यायिक प्रणाली में मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए सबसे गंभीर चुनौतियों में से एक है।

जस्टिस सराफ ने कहा कि यह 'हैरान करने वाली' बात है कि हमारे भारतीय संविधान में गैर-कानूनी हिरासत या हिरासत में मौत के लिए मुआवज़ा देने का कोई साफ़ आदेश नहीं है। कोर्ट ने आगे कहा कि अगर हिरासत में मौत प्राकृतिक होती है तो राज्य को इसके लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता। लेकिन, अगर मौत अप्राकृतिक हुई है तो राज्य अपने उस काम/चूक के लिए पूरी तरह से ज़िम्मेदार है जिसके कारण किसी व्यक्ति की मौत हुई।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रुदुल साह बनाम बिहार राज्य मामले में सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले पर भी भरोसा किया, जिसमें कहा गया कि बुनियादी अधिकारों से वंचित करने पर मुआवज़े का आदेश देने से इनकार करना आज़ादी के अधिकार के प्रति सिर्फ़ दिखावटी वादा करना होगा।

कोर्ट ने नीलाबती बेहरा बनाम उड़ीसा राज्य और डी.के. बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य में सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को भी ध्यान में रखा, जिसमें यह कहा गया कि पैसे की भरपाई स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के सिद्धांत पर आधारित एक सही और असरदार उपाय है, जिसके लिए सॉवरेन इम्यूनिटी का बचाव मौजूद नहीं है।

खास तौर पर मुआवज़े की रकम तय करते समय कोर्ट ने मेघालय हाईकोर्ट के एक फैसले (सुओ मोटो कस्टोडियल वायलेंस) की जांच की, जिसमें पीड़ित की उम्र के आधार पर मुआवज़े को श्रेण में बांटा गया। हालांकि, डिवीजन बेंच ने इसे आधिकारिक मिसाल के तौर पर मानने से यह देखते हुए इनकार किया कि उस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने मेघालय राज्य बनाम किलिंग जाना में रोक लगा दी थी।

इस पृष्ठभूमि में कोर्ट ने बिना किसी विवाद वाले रिकॉर्ड से नोट किया कि मृतक राज्य की कस्टडी में था और उसने आत्महत्या कर ली थी। बेंच ने कहा कि हो सकता है कि उसके आस-पास ऐसे हालात रहे हों, जिनकी वजह से उसने इतना बड़ा कदम उठाया, लेकिन मरने वाले की अप्राकृतिक मौत के लिए राज्य पूरी तरह से ज़िम्मेदार है।

खंडपीठ ने कहा, "...पुलिस की हिरासत में किसी कैदी की मौत के लिए राज्य की ज़िम्मेदारी बढ़ जाती है। कोई भी राज्य कैदियों को बेहतर सुविधाएं देने की अपनी ज़िम्मेदारियों से बच नहीं सकता। इसलिए इस मामले में हिरासत में मौत का मामला बनता है।"

इसे देखते हुए कोर्ट ने यह नतीजा निकाला कि यह संवैधानिक सुरक्षा का साफ़ उल्लंघन था, जिसके लिए संविधान के आर्टिकल 226 के तहत दखल देना ज़रूरी है। इसलिए कोर्ट ने रिट पिटीशन मंज़ूर कर ली और राज्य को तीन हफ़्ते के अंदर कानूनी वारिसों को मुआवज़े के तौर पर ₹10,00,000 देने का निर्देश दिया।

सिस्टम में सुधार लाने के लिए एक कदम और आगे बढ़ते हुए कोर्ट ने भविष्य में कस्टोडियल डेथ के सभी मामलों में सख्ती से पालन किए जाने वाले चार शुरुआती कदम बताए:

अ) जेल अधिकारियों को मृतक के परिवार वालों को मृतक की मौत के बारे में तुरंत बताना होगा। बिना किसी देरी के सीआरपीसी की धारा 174 (बीएनएसएस की धारा 194) के अनुसार, मौके पर ही स्वतंत्र पंचों के साथ एक पंचनामा तैयार किया जाएगा।

ब) बिना किसी देरी के मौत का कारण बताते हुए तुरंत पोस्टमॉर्टम जांच की जानी चाहिए। मृतक की हिरासत में मौत के मामले में पोस्टमॉर्टम जांच की वीडियो रिकॉर्डिंग ज़रूरी तौर पर की जानी चाहिए।

स) सभी गवाहों, पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट और पंचनामा पर विचार करने के तुरंत बाद सीआरपीसी की धारा 176 (बीएनएसएस की धारा 196) के अनुसार संबंधित ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट द्वारा जांच रिपोर्ट जमा की जानी चाहिए।

द) हिरासत में मरने वाले के परिवार वालों को सांत्वना देने के लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा तय किया गया मुआवज़ा, हर मामले के खास तथ्यों और हालात पर विचार करने के बाद दिया जाना चाहिए।